



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15, 1994/पौष 25, 1915

No. 3]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15, 1994/PAUSA 25, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-Section (II)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ  
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministry of the Government of India (other than  
Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(विधि कार्य विभाग)

न्यायिक खंड  
सूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1993

नं. आ. 106.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री इकबाल सिंह एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी की उक्त नियम के नियम 4 के अर्धीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे नवां शहर, जलंधर जिला (पंजाब) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(127)/93--स्वायिक]

पी. सी. कन्नन, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS  
(Department of Legal Affairs)

JUDICIAL SECTION

NOTICE

New Delhi, the 7th December, 1993

S.O. 106.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4

of the said Rules, by Sh. Iqbal Singh Gill, Advocate for appointment as a Notary to practice in Nawanshar Sub Division, Distt. Jalandhar (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(127)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1993

का.आ. 107—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री नृपम चन्द खोबर एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी की उक्त नियम के नियम 4 के अर्धीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे राहना (हरियाणा में) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(133)/93--स्वायिक]

पी. सी. कन्नन, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 14th December, 1993

S.O. 107.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that

application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Hukam Chand Khokhar, Advocate for appointment as a Notary to practice in Rohtak (Haryana).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5. (133)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1993

का. आ. 108.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री निरंजन दास राहल एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे फागवाड़ा, जिला बधूरखवा (पंजाब) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(136)/93-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

#### NOTICE

New Delhi, the 14th December, 1993

S.O. 108.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Niranjana Das Rahl, Advocate for appointment as a Notary to practise in Phagwara, Distt. Kapurthala (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5. (130)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1993

का. आ. 109.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री के. एन. बालाशंकर एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(131)/93-न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

#### NOTICE

New Delhi, the 14th December, 1993

S.O. 109.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. K. S. Balashankara, Advocate for appointment as a Notary to practise in Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5. (131)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1993

का.आ. 110.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री जगदीश चन्द्र विजयवर्गिया एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे भीलवाड़ा (राजस्थान) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(132)/93-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

#### NOTICE

New Delhi, the 14th December, 1993

S.O. 110.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Jagdish Chandra Vijayvargia Advocate for appointment as a Notary to practise in Bhilwara (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5. (132)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1993

का.आ. 111.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सेवा राम शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे गाझियाबाद (उ.प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(128)/93-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

#### NOTICE

New Delhi, the 15th December, 1993

S.O. 111.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Sewa Ram Sharma, Advocate for appointment as a Notary to practise in Ghaziabad (U.P.).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5 (128)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1993

का.आ. 112.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री गिरीश रामचन्द्र शर्मा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे शिवगंजी जिला थाने (महाराष्ट्र राज्य) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के

रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[नं. 5(136)/93-न्यायिक]  
पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

### NOTICE

New Delhi, the 20th December, 1993

S.O. 112.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Shirish Ram Chandra Sane, Advocate for appointment as a Notary to practise in Bhiwandi, Dist. Thane (Maharashtra).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5. (136)/93 Judl.]  
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1993

का.श्रा. 113—नोटरीय नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण से सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री शरिश राम चंद्र सने एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अर्धीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे तेरह नंबर नियम कम्पाउंड (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[नं. 5(135)/93-न्यायिक]  
पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

### NOTICE

New Delhi, the 20th December, 1993

S.O. 113.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Naresh Chand Jain, Advocate for appointment as a Notary to practise in Meerut Municipal Board Compound (U.P.).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(135)/93-Judl.I]  
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1993

का.श्रा. 114—नोटरीय नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण से सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री मोतीलाल शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अर्धीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे जिला बन्दर (राजस्थान) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[नं. 5(137)/93-न्यायिक]  
पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

### NOTICE

New Delhi, the 20th December, 1993

S.O. 114.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Moti Lal Sharma, Advocate for appointment as a Notary to practise in Alwar Distt. (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5. (137)/93-Judl.]  
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1993

का.श्रा. 115—नोटरीय नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण से सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अरुण शर्मा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अर्धीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे जालंधर (पंजाब राज्य) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(134)/93 न्यायिक]  
पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

### NOTICE

New Delhi, the 20th December, 1993

S.O. 115.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Arun Sharma, Advocate for appointment as a Notary to practise in Jalandhar (Punjab).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(134)/93-Judl.II]  
P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1993

का.श्रा. 116—नोटरीय नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण से सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अशित बसु एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अर्धीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे मालदा (पश्चिम बंगाल) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(139)/93-न्यायिक]  
पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

### NOTICE

New Delhi, the 21st December, 1993

S.O. 116.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Asit Baran Basu, Advocate for appointment as a Notary to practise in Malda (West Bengal).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5. (139)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1993

का.प्रा. 117--नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री अशोक कुमार साहा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे नार्थ 24 पार्गना (पश्चिम बंगाल) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(138)/93-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

#### NOTICE

New Delhi, the 21st December, 1993

S.O. 117.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Ashok Kumar Saha, Advocate for appointment as a Notary to practise in North 24, Pargana (West Bengal).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5. (138)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1993

का.प्रा. 118--नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री वेद प्रकाश वर्मा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे मेरठ कमिश्नरी (उत्तर प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(141)/93-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

#### NOTICE

New Delhi, the 23rd December, 1993

S.O. 118.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Ved Prakash Varma, Advocate for appointment as a Notary to practise in MEERUT Commissionary (U.P.).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5. (141)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1993

का.प्रा. 119--नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री कान्तिशाल के सक्ती एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम

के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे बुधवार, शुकवार एवं सदाशिव पेंठ (पुणे) महाराष्ट्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(142)/93-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

#### NOTICE

New Delhi, the 23rd December, 1993

S.O. 119.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Sh. Kantilal K. Sancheti, Advocate for appointment as a Notary to practise in Budhwar, Shunkrawar and Sadashiv Peth (Pune) Maharashtra.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(142)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1993

का.प्रा. 120--नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सुश्री पुष्पा गुप्ता एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे जिला पार्लपत (हरियाणा) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये।

[सं. 5(140) 93-न्यायिक]

पी.सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

#### NOTICE

New Delhi, the 23rd December, 1993

S.O. 120.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by Miss Pushpa Gupta, Advocate for appointment as a Notary to practise in District Panipat (Haryana).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5. (140)/93-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

सूचना

नई दिल्ली, 24 दिसंबर, 93

का.प्रा. 121--नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सुश्री अविनाश कौर, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे पटियाला हाउस कोर्ट कांफ्लेक्स, दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(132)/92 न्यायिक]

पी. सी. कण्णन, सक्षम प्राधिकारी

## NOTICE

New Delhi, the 24th December, 1993

S.O. 121.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that application has been made to the said Authority, under Rule 4 of the said Rules, by M/s. Avinash Kaur Advocate for appointment as a Notary to practise in Patiala House Courts Complex, New Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5. (132)/92-Judl.]

P. C. KANNAN, Competent Authority

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1993

का.प्र. 122 —केंद्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से, जो गृह (एम.सी.ए.) विभाग जी.ओ.आर.टी. सं. 1322, तारीख 29-5-1993 द्वारा प्रवान की गई थी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रजिस्ट्रीकृत आर. साईबाबरम सी. 4(ए)/93-विशाखापट्टनम, तारीख 30-4-1993 में नीचे उपदिष्ट सुसंगत अधिनियमों के उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराधों और उक्त अपराधों तथा वैम ही और/या उन्नी या उनसे संबंधित तथ्यों से उद्भूत होने वाले संश्लेषण के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराधों के संबंध में या उनसे सम्बन्ध प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्र के, जिनके बारे में यह अभिकथन है कि वे निम्नलिखित प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के मदद्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण आन्ध्र प्रदेश राज्य पर करती है।

आर.सी.सं. और विधियों की धाराएं	अभियुक्त व्यक्तियों के नाम
1	2
भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 420, 467, 468 और 471 के साथ पठित धारा 120 के अधीन और छप्पाबार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (ख) के साथ पठित 13(2) के अधीन आर. सी. 4(ए)/93-बी.एम.पी. तारीख 30-4-93	1. जी. वेंकटेश्वरलु, सेवा निवृत्त आयकर अधिकारी, वार्ड-7, विजयवाड़ा। 2. आर. राघवैया, ठेकेदार, नवरंग टाकीज के समीप, म.सं. 10-4-321 गवर्नरपेट, विजयवाड़ा। 3. बी. कोडू, ठेकेदार रामामंदीराम स्ट्रीट, म.सं. 10/42, विजयवाड़ा। 4. टी. रामाबायू, ठेकेदार, सूर्यरावपेट म.सं. 4-3-125, विजयवाड़ा। 5. के. रामाराव, ठेकेदार, सूर्यरावपेट म.सं. 6-2-142 विजयवाड़ा। 6. डेरीलेट्टी, रामलु, ठेकेदार, साइलावरम। 7. चि. वेंकटेश्वरलु, ठेकेदार सूर्यरावपेट म.सं. 2/86, विजयवाड़ा। 8. के. रामय्या सुपुत्र बुचय्या, ठेकेदार, साइलावरम।

9. बी. माजबुनु, ठेकेदार, म. सं.

10/120, सूर्यरावपेट, विजयवाड़ा।

10. बी. कोडूय्या, ठेकेदार, गवर्नरपेट, म.सं. 27-23-145, नवरंग टाकीज के समीप, विजयवाड़ा।

11. पी. रामय्या सुपुत्र हनुमंत राव ठेकेदार, गल्ल हार्ड स्कूल के समीप, साइलावरम।

12. कांगानुवा श्रीनु, ठेकेदार, साइलावरम।

13. बी. नागय्या, मार्फत हनुमंत राव ठेकेदार, गल्ल हार्ड स्कूल के समीप, साइलावरम।

14. एम. अन्ना राव, मार्फत बुगावर प्लास्टिक वर्कर्स, गांधी नगर, विजयवाड़ा।

15. श्रीमती जी. लक्ष्मी वल्ली जयपाल अंडावल्ली स्ट्रीट, विजयवाड़ा।

16. टी. हनुमंत राव सुपुत्र टी. अजय्या ठेकेदार, साइलावरम।

और अन्य व्यक्ति जिन्होंने उपर्युक्त व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र किया है।

[सं. 228/76/93-ए.बी.डी.-II]

आर.एम. बिष्ट, अवसर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL  
PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel &amp; Training)

New Delhi, the 13th December, 1993

S.O. 122.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) the Central Government, with the consent of the State Government of Andhra Pradesh accorded vide Home (SC-A)/Department G.O. Rt. No. 1322 dated 29-5-1993 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for investigation of the offences in RC 4(A)/93-Visakhapatnam 30-4-1993 registered by Central Bureau of Investigation and attempts, abetments conspiracy in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction and or arising out of the same or related facts, punishable under the provisions of relevant acts indicated below alleged to have been committed by the following private persons.

RC No. & Secs. of Laws.	Name of the accused persons
1	2
RC 4(A)/93-VSP. dated 30-4-1993 U/S, 120 B r/w 420, 467, 468 and 471 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860). and U/S 13(2) r/w 13(1) (d) of P.C. Act, 1988.	1. G. Venkateswarlu Rtd. I.T.O. Ward-7 Vijayawada. 2. R. Raghavaiah, Contractor Near Navarang Talkies H. No. 10-4-321, Governorpet, Vijayawada.

1

2

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1993

3. V. Konddu,  
Contractor Ramamman-  
diram Street,  
H. No. 10/42,  
Vijayawada.
4. T. Ramababu,  
Contractor Suryaraopat  
H. No. 4-3-125,  
Vijayawada.
5. K. Rama Rao,  
Contractor Suryaraopat,  
H. No. 6-2-142,  
Vijayawada.
6. Tarriseti Ramulu,  
Contractor,  
Mylavaram
7. Ch. Venkateswarlu,  
Contractor, Suryaraopat,  
H. No. 2/86,  
Vijayawada.
8. K. Ramaiah S/o Butchaiah  
Contractor, Mylavaram;
9. B. Sajaneyulu  
Contractor,  
H. No. 10/120,  
Suryaraopat,  
Vijayawada.
10. B. Kondaiah,  
Contractor,  
Governorpet,  
H. No. 27-23-145,  
Near Navarang Talkies,  
Vijayawada.
11. P. Ramaiah S/o  
Hanumantha Rao,  
Contractor,  
Near Girl's High School,  
Mylavaram.
12. Konaganula Sreenu,  
Contractor,  
Mylavaram,
13. B. Nagaiah  
C/o Hanumantha Rao,  
Contractor,  
Near Girls' High School,  
Mylavaram.
14. M. Appa Rao  
C/o Bugadar Plastic Works  
Gandhi, Nagar  
Vijayawada.
15. Smt. G. Lakshmi  
W/o Jayapal,  
Undavalli Street,  
Vijayawada.
16. T. Hanumantha Rao  
S/o T. Anjaiah,  
Contractor,  
Mylavaram.

and other persons who have  
conspired with the above.

[No. 228/76/93-AVD. II]

R.S. BISHT, Under Secy.

का.प्रा. 123 — केन्द्र सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरप्रदेश के होम (पुलिस) धारा 10 सं. 124/बीएच ए/6-पी-10-93-27(45)/93 लखनऊ दिनांक 21-12-93 एनडूबारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित अपराधों तथा मामलों को ग्रामे भ्रमण के लिए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के मदद्यों की शक्तियों तथा अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में करती है।

2301 अप और 2302 डाउन राजधानी एक्सप्रेस में हुए नम विस्फोटों से संबंधित मामले;

(1) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 और जेल अधिनियम की धारा 151 के अन्तर्गत दर्ज पुलिस स्टेशन जी आरपी, कानपुर की एक.आई.पार. सं. 595/93, और

(2) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत दर्ज पुलिस स्टेशन जी आरपी, कानपुर की एक.आई.पार. सं. 765/93 और

(ख) प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों से संतुष्ट एक अथवा एक से अधिक ऊपर उल्लिखित अपराधों तथा कोई अन्य अपराध अथवा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी ऐसे अपराधों के संव्यवहार में।

[सं. 228/83/93—एवीडी-11]

पराग प्रकाश, उप सचिव

New Delhi, the 22nd December, 1993

S.O. 123.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Govt. with the consent of the State Govt. of Uttar Pradesh vide Home (Police) Section-10 No. 124/BHA/6-p-10-27(45)/93 Lucknow dated 21-12-93 herewith extends the powers and jurisdiction of the member of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for further investigation of the following cases and offences :—

(1) FIR No. 595 of 93 of P. S. GRP, Kanpur u/s 3/4 of the Explosive Substances Act and u/s 151 Railway Act, and

(2) FIR No. 765/93 of P. S. GRP Kanpur u/s 3/4 of the Explosive Substances Act.

registered in connection with the bomb blasts that occurred in 2301 UP and 2302 DN Rajdhani Express, and

(b) attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with one or more offences mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/83/93-AVD-II]  
PARAG PRAKASH, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1993

का.प्रा. 124— कानून और प्रशासन विभाग को दिनांक 22-12-93 की पहिले की अधिसूचना सं. 228/83/93-एवीडी-II के अधिनियम अधिनियम में केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पत्र सं. गृह (पुलिस) अनुभाग 10 सं. 24/बीएचए/

6-10-93-27 (45)/93-लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 1993 द्वारा प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार निम्नलिखित मामलों के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है:—

1. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 और रेल अधिनियम की धारा 151 के अन्तर्गत धाना जीआरपी कानपुर का अपराध सं० 595/93, और

2. 5/6 दिसम्बर, 1993 को 2301 अप और 2302 डाउन राजधानी एक्सप्रेस में हुए बस विस्फोटों के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत धाना जीआरपी इलाहाबाद के अपराध सं० 765 के स्थानांतरण पर धाना जीआरपी कानपुर में पुनः रजिस्टर्ड अपराध सं० 597/93, तथा

(ख) ऊपर बणित अपराधों में से किसी एक या अधिक अपराधों और उम्मीदवारों और परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संभवहारों के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध या अपराधों के संबंध में या उनसे संगत प्रयत्न, दुष्प्रेरण और पड़ोस ।

[सं. 228/83/93-एवीडी-II]  
पराग प्रकाश, उप सचिव

New Delhi, the 29th December, 1993

S.O. 124.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Govt. in partial modification of earlier DP&Trg. Notification No. 228/83/93-AVD.II dated 22-12-93 with the consent of the State Govt. of Uttar Pradesh vide Home (Police) Section 10 No. 24/BHA/6-10-93-27(45)/93 Lucknow dated 27th December 1993 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for the investigation of the following cases:—

1. Crime No. 595/93 of P. S. GRP Kanpur u/s 3/4 of the Explosive Substances Act and Section 151 of the Railway Act and
2. Crime No. 597/93 P. S. GRP Kanpur re-registered on transfer of Crime No. 765/93 PS GRP Allahabad u/s 3/4 of the Explosive Substances Act relating to the Bomb Blasts that occurred in 2301 UP and 2302 DN Rajdhani Express on 5/6 December 1993 and.

(b) attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with one or more of the offences mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts and circumstances.

[No. 228/83/93-AVD.II]  
PARAG PARKASH, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1993

का.धा. 125. — केन्द्रीय सरकार, आलंकादी तथा विषटनकारी क्रियाकलापों (निरोधी) अधिनियम, 1987, 1987 का अधिनियम सं. 28 की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा सर्वथा एम. के. सक्सेना, अपर विधि सलाहकार, एस.एन. निवारी, उपविधि सलाहकार और एस.सी. शर्मा, वरिष्ठ लोक अभियोजक, के.प्र. ब्यूरो, दिल्ली को अनुसूची में उल्लिखित मामलों

और ऐसे क्षेत्रों में हूँ बने मामले, जो बम्बई नगर और उसके उपनगरों में 12 मार्च, 1993 को हुए बम विस्फोटों से संबंधित हों तथा इनके साथ संबंधित हो अथवा उक्त अधिनियम के अंतर्गत अन्य आनुवंशिक मामलों में नामित बम्बई न्यायालय में अभियोजन के लिए उद्युक्त अभियोजन के लिए उद्युक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत बम्बई नगर और बम्बई उपनगरीय जिलों, रायगढ़ जिला या जिला जैसा कि उद्युक्त अनुसूची में उल्लिखित है, में घटित अपराधों अथवा हुए मामलों के लिए तथा इन क्षेत्रों में उक्त बम विस्फोटों के ऐसे किसी भी मामलों के विचारण के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

अनुसूची

क्रम.सं.	स्थान	पुनित स्टेशन और सं. आर.नं.	डी.सं.बो. सं. आर.नं.
1	2	3	4
1.	स्टॉक एक्सचेंज	एम.आर.ए. मार्ग, 129/93	70/93
2.	करवा बाजार	पैरीग्रुईन, 193/93	73/93
3.	सेना भवन	दादर, 186/93	118/93
4.	सेन्सुरी बाजार	दादर, 187/93	117/93
5.	महिम कॉम्पे	महिम, 185/93	110/93
6.	एयर इन्डिया	कूफे पराडे, 126/93	71/93
7.	जावेरी बाजार (एक्सप्लोडिब स्कूटर)	एल.टी. मार्ग, 122/93	75/93
8.	सं.नं. कहांटल	बान्द्रा, 148/93	114/93
9.	प्लाजा सिनेमा	महिम, 184/93	189/93
10.	जूहू सेंटर होटल	सातनाकूज, 155/93	116/93
11.	एयरपोर्ट वे 54 (ओरिएण्टल ए.जी.)	सह्या, 200/93	108/93
12.	सेंट्रल होटल (एयरपोर्ट)	एयरपोर्ट, 19/93	115/93
13.	बर्ली	बर्ली, एल.एस. 389/93	112/93
14.	नैगम सं. आर.एस. रोड (अन एक्सप्लोडिब स्कूटर)	मत्तंगा, 251/93	73/93
15.	धनजी स्ट्राट पंड जावेरी बाजार (2 अतः एक्सप्लोडिब स्कूटर)	एल.टी. मार्ग, 124/93	111/93
16.	महामला	महामला, 6/93	132/93
17.	श्रीवार्धन	श्रीवार्धन, 14/93	133/93
18.	गोरेगांव	गोरेगांव, 17/93	134/93
19.	धाने	कपूर बावडे, 14/93	135/93
20.	एम.के. रोमन स्ट्रीट	एल.टी. मार्ग, 138/93	77/93
21.	इस्टर्न साईड लेकोटरी ऑफ म्साफिन खाना, बम्बई		एल.एस. 15/93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	नरियाल वाडी, मुस्लिम सेमेटरी, मलगांव		एन.टी.सी. 18/93		4.	Century Bazar	Dadar, 187/93	117/93
23.	पिकनिक गेस्ट हाऊस नियर लीडो थियेटर, सन्ताक्रुज (इस्ट)		एन.सी. 20/93		5.	Mahim Causeway	Mahim, 185/93	110/93
24.	58, नर्गिस दुत्ता रोड, पाली हिल, बान्द्रा (प.) बम्बई-50		एन.सी. 21/93		6.	Air-India	Cuffe Parade 126/93	71/93
25.	बोनापार्ट इन्डस्ट्रीज, घनश्याम इन्डस्ट्रीज इस्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी		एन.सी. 23/93		7.	Zaveri Bazar (Exploded Scooter)	LT Marg, 122/93	75/93
26.	खातीजाबी चौक आर.मं. 1 सोनापुर, वेन कृष्णा (प.)	कृष्णा, एन.सी. 707/93	एन.सी. 32/93		8.	Sea-Rock Hotel	Bandra, 148/93	114/93
27.	ई.मलैक कॉ. प्रापोजिट एन.सी.एस.सी.टी. मिलेट्री रोड, भंगेल, बम्बई		एन.सी. 22/93		9.	Plaza Cinema	Mahim, 184/93	109/93
					10.	Juhu Centaur Hotel	Santacruz, 155/93	116/93
					11.	Airport Bay 54 (Throwing H.G.)	Sakar, 200/93	108/93
					12.	Centaur Hotel (Airport)	Airport, 19/93	115/93
					13.	Worli	Worli, LAC 389/93	112/93
					14.	Naigaum C.R.S. Rd. (Unexpl. Scooter)	Matunga, 251/93	72/93
					15.	Dhanji ST & Zaveri Bazar (2 unexploded scooter)	L.T. Marg, 124/93	111/93
					16.	Mhasla	Mhasla, 6/93	132/93
					17.	Shrivardhan	Shivardhan, 14/93	133/93
					18.	Goregaon	Goregaon 17/93	134/93
					19.	Thane	Kapurbawadi, 14/93	135/93
					20.	S.K. Memon Street	L.T. Marg, 138/93	77/93
					21.	Eastern Side Lavatory of Musaffir Khana, Bombay.		LAC 15/93
					22.	Nariyal Wadi. Muslim Cementary. Mazgaon.		LAC 18/93
					23.	Picnic Guest House Near Lido Theatre, Santacruz (W)		LAC 20/93
					24.	58, Nargis Dutta Rd., Pali Hill, Bandra (W) Bombay-50.		LAC 21/93
					25.	Bona Part Ind., Ghanshyam Indl. Est. Vira Desai Rd., Andheri.		LAC 23/93
					26.	Khatijabi Chawl R. No. 1 Sonapur Lane Kurla(W).	Kurla, LAC 707/93	LAC 32/93
					27.	Dreamland Co. Op. Hsg. Sct. Military Rd., Marol, Bombay.		LAC 22/93

[मं. 225/46/93-ए.वी.डी.-II]  
भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा,  
बी. लक्ष्मीरत्न, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th December, 1993

S.O. 125 :—In exercise of the powers conferred by sub-Section (i) of Section 13 of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987, Act No. 28 of 1987, the Central Government hereby appoints S/Shri S.K. Saxena, Additional Legal Adviser, S.N. Tewari, Deputy Legal Adviser and C.S. Sharma, Senior Public Prosecutor, Central Bureau of Investigation, Delhi as Special Public Prosecutors for conducting prosecution of the cases mentioned in the schedule appended hereto, and such cases in such areas as may arise out of and connected with Bomb blasts which occurred on 12th March, 1993 at Bombay City and suburbs, and other matters connected therewith or incidental thereto under the said Act in the Designated Court at Bombay constituted u/s 9 of the said Act to try offences or such cases committed at Bombay city and Bombay suburban Districts, Raigad District and Thane District as mentioned in the said Schedule, and to try such cases in such areas as may arise out of and connected with aforesaid Bomb Blasts.

#### SCHEDULE

Sr. No.	Place	Police Station and C.R. No.	D.C.B. Cr. No.
1	2	3	4
1.	Stock Exchange	M.R.A. Marg, 129/93	70/93
2.	Katha Bazar	Pydhonie, 195/93	73/93
3.	Sena Bhawan	Dadar, 186/93	118/93

[No. 225/46/93—ADV. II]  
By order and in the name of  
the President of India,  
V. LAKSHMI RATAN, Jt. Secy.

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धित

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1993

(आयकर)

का.भा. 126 -- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-सी) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ दिनांक 26-2-92 को जारी अधिसूचना संख्या 9004 (फा.सं. 197/206/91-आयकर नि-1) में निम्नलिखित संशोधन करती है:--

- (1) कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक के स्थान पर  
(1) कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए पढ़ा जाए।

[अधिसूचना सं. 9210/फा.सं. 197/206/91-आयकर (नि.-1)]

शरत चन्द्र, धनर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th February, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 126.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following modification in its notification No. 9004 (F. No. 197/206/91-ITA-I) dated 26-2-92 notifying "Hindu Satkar Samity, Calcutta" for the purpose of the above said clause:—

For : (i) for the assessment years 1992-93 to 1995-96.

Read : (i) for the assessment years 1990-91 to 1992-93.

[Notification No. 9210/F. No. 197/206/91-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1993

(आयकर)

का.भा. 127 -- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्री विठ्ठलदास बामोदर ठाकरसी चैरिटेबल ट्रस्ट बंबई" को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:--

- (1) कर निर्धारिणी उसकी आय का हस्तेमाल अथवा इसकी आय का हस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है।
- (2) कर निर्धारिणी ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अवधि एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंगदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में भलग से लेखापुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9220/फा. सं. 197/145/92-आयकर (नि.-1)]

शरत चन्द्र, धनर सचिव

New Delhi, the 19th February, 1993

## (INCOME-TAX)

S.O. 127.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sir Vithaldas Damodar Thackersay Charitable Trust, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9220/F. No. 197/145/92-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1993

(आयकर)

का.भा. 128 -- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "आश्रम, बंगलौर" को कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है अर्थात्:--

- (1) कर निर्धारिणी इसकी आय का हस्तेमाल अथवा इसकी आय का हस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (2) कर निर्धारिणी ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अवधि एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंगदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो

जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में श्रवण से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9219/फा. सं. 197/149/91-आयकर नि.-1]

शरत चन्द्र, अधीक्षक सचिव

New Delhi, the 19th, February, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 128.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Ashraya, Bangalore" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1991-92 to 1993-94 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9219/F. No. 197/149/91-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 129 —आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "दि सोसायटी आफ दि फॉरिस्टर सर्वेंट्स आफ मेरी, सेलम, तमिलनाडु" को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर निर्धारिणी इसकी आय का हस्तमाला अथवा इसकी आय का हस्तमाला करने के लिए इसका संवयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर निर्धारिणी ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों में इसकी निधि (जैवर, जवाहिरान, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में श्रवण से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9229/फा. सं. 197/4/93-आयकर (नि.-)]

शरत चन्द्र, अधीक्षक सचिव

New Delhi, the 1st March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 129.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Society of the Franciscan Servants of Mary, Salem, Tamil Nadu" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1989-90 to 1991-92 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9229/F. No. 197/4/93-ITA-II]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली 1 मार्च 1993

(आयकर)

का.आ. 129 —आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "दि नेशनल एसोसिएशन फॉर दि फ्रान्सीस्कन सर्वेंट्स ऑफ मेरी" को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर निर्धारिणी इसकी आय का हस्तमाला अथवा इसकी आय का हस्तमाला करने के लिए इसका संवयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर निर्धारिणी ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों में इसकी निधि (जैवर, जवाहिरान, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में श्रवण से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9227/फा. सं. 197/20/93-आयकर (नि.-1)]

शरत चन्द्र, अधीक्षक सचिव

New Delhi, the 1st March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 130.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby

notifies "The National Association for the Blind, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9227/F. No. 197/20/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 131 :- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन्ड्रस "दि नेशनल ब्लाइन्ड सोसाइटी, अदयार, मद्रास" का कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसे इस उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) कर-निर्धारिता इसकी आय का इस्तेमाल अपना इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिता ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों का कितां भा अधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरकों में भिन्न तरकों में इसकी निधि (जेवर-जवाहिरान, फर्निचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंगदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना कितां ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अन्तिम के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उस कर-निर्धारिता के उद्देश्यों का प्राप्ति के लिए प्राप्त नहीं हो तथा ऐसी कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जायें हों ।

[अधिसूचना सं. 9228 फा.सं. / 197/6/93-आयकर (नि.-1)]  
शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 1st March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 131—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Action for Food Production, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1988-89 to 1990-91 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9227/F. No. 197/6/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 132 :- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन्ड्रस "दि थियोसोफिकल सोसाइटी, अदयार, मद्रास" का कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसे इस उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) कर-निर्धारिता इसकी आय का इस्तेमाल अपना इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिता ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों का कितां भा अधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरकों में भिन्न तरकों में इसकी निधि (जेवर-जवाहिरान, फर्निचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंगदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना कितां ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अन्तिम के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उस कर-निर्धारिता के उद्देश्यों का प्राप्ति के लिए प्राप्त नहीं हो तथा ऐसी कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जायें हों ।

[अधिसूचना सं. 9232 फा.सं. 197/127/93-आयकर (नि.-1)]  
शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd March, 1993  
(INCOME-TAX)

S.O. 132.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the Theosophical Society, Adyar, Madras for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and

maintained in the form of jewellery, furniture etc. for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9232/F. No. 197/127/92-ITA]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1993

भायकर

का.भा. 133 :—भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "दि एनीबेसेंट ट्रस्ट, अदयार, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारित इसको आय का इस्तेमाल याता यातन या का इस्तेमाल करने के लिए इसका संयोजन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारित ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों का किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अवधि एक से अधिक ढंग अवधि तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक भंडारण से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसे आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाष के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारितों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखा जाता हों ।

[अधिसूचना सं. 9233/का.सं. 197/129/92-भायकर (नि.-I)]  
शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd March, 1993  
(INCOME-TAX)

S.O. 133.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the Annie Besant Trust, Adyar, Madras for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9233/F. No. 197/129/92-ITA]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1993

भायकर

का.भा. 134 :—भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "टी.टी. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउण्डेशन, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारित इसको आय का इस्तेमाल अथवा इसका आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संयोजन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारित ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों का किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अवधि एक से अधिक ढंग अवधि तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक भंडारण से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसे आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाष के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारितों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9235/का.सं. 197/33/93-भायकर (नि.-I)]  
शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 5th March 1993  
INCOME-TAX

S.O. 134.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "T. T. Ranganathan Clinical Research Foundation, Madras" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9235/F. No. 197/33/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 135—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उपखण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्ण तथा तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिणी ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक उक्त अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जैसे- जवाहिरान, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- ( ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलास के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9236/फा.सं. 197/123/91-आयकर (नि.-1)]

शरत चन्द्र, अधर सचिव

New Delhi, the 5th March, 1993

(INCOME-TAX)

New Delhi, the 5th March, 1993

S.O. 135.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Lady Tata Memorial Trust, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9236/F. No. 197/123/91-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 136 :- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "दि म्यूजिक एकादमी मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है :-

- ( ) कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- ( ) कर-निर्धारिणी ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक उक्त अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जैसे- जवाहिरान, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त रख-रखाव में अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- ( ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलास के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9239/फा.सं. 197/52/93-आयकर (नि.-1)]

शरत चन्द्र, अधर सचिव

New Delhi, the 10th March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 136.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Music Academy, Madras" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9239/F. No. 197/52/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 137 :- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "जमनालाल बजाज फाउंडेशन, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक के लिए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 9243/फा.सं. 197/151/84-आयकर नि. 1)]

शरत चन्द्र, अधर सचिव

New Delhi, the 15th March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 137.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Jammalal Bajaj Foundation, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1985-86 to 1989-90.

[Notification No. 9243/F. No. 197/151/84-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1993

(आयकर)

का.भा. 138.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उपखण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "जमनालाल बाजज फाउंडेशन, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्य-तथा उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिणी ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक धंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वीच्छक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9244 /फा.सं. 197/151/84-आयकर नि.-1]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 15th March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 138.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Jammalal Bajaj Foundation, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the

objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9244/F. No. 197/151/84-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1993

(आयकर)

का.भा. 139.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उपखण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिणी ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक धंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वीच्छक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी । जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9252/फा.सं. 1975/3/93-आयकर नि. -1]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 139.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Bharatiya Bhasha Parishad, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9252/F. No. 197/53/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1993

आयकर

का.आ. 140:- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए जमशेदपुर कल्याण संसाधन, जमशेदपुर" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (i) कर-निर्धारित इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्य-तया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारित ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों को किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जवर-जवाहिरान, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक भ्रमण से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाष के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9253/फा.सं. 197/2/93-आयकर (नि.-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 140.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Jamshedpur Society for the Welfare of Mentally Retarded Children, Jamshedpur" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1988-89 to 1990-91 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9253/F. No. 197/2/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 141:- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए जमशेदपुर कल्याण संसाधन, जमशेदपुर" को कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात :-

- (i) कर-निर्धारित इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर निर्धारित ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों को किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जवाहिरान, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक भ्रमण से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाष के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9254/फा.सं. 197/2/93-आयकर (नि.-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 141.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Jamshedpur Society for the Welfare of Mentally Retarded Children, Jamshedpur" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1991-92 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9254/F. No. 197/2/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 142:- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "कार्मिल फार एडवांस्-मैंट ऑफ पोपुलम एक्शन एंड काल टेक्नासॉजी, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक के लिए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[अधिसूचना सं. 9256/फा.सं. 197/2/93-आयकर (नि.-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 1993  
(INCOME-TAX)

S.O. 142.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Council for Advancement of People's Action & Rural Technology, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1987-88 to 1989-90.

[Notification No. 9256/F. No. 197/213/86-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 143 :- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन.डी.आर. "काउंसिल फॉर एडवेंसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) कर-निर्धारिता इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिता ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक वस्तु अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जैसे- जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में खर्चिक अंशदान में भिन्न) का निवेश नहीं करेगा, अथवा उसे जमा नहीं करना सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखापुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9257/फा.सं. 197/213/86 आयकर (वि. 1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

(INCOME-TAX)

New Delhi, the 30th March, 1993

S.O. 143.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Council for Advancement of People's Action & Rural Technology, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the

objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9257/F. No. 197/213/86-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 144 :- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन.डी.आर. "केरल लेबर वेलफेयर फंड बोर्ड, केरल" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) कर-निर्धारिता इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिता ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक वस्तु अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जैसे- जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में खर्चिक अंशदान में भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करना सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखापुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना संख्या 9258/फा.सं. 197/201/91 आयकर (वि. 1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 144.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Kerala Labour Welfare Fund Board, Kerala" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9258/F. No. 197/201/91-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 145 :- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "एस. जे. जिनदल ट्रस्ट बंगलूर" को कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) कर-निर्धारित इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संयोजन पूर्णतया तथा अलग-अलग उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारित ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जैवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिताम के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9259/फा.सं. 197/102/92-ITA-I]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 1993

## INCOME-TAX

S.O. 145.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "S. J. Jindal Trust, Bangalore" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1991-92 to 1993-94 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9259/F. No. 197/102/92-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 146 :- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "मोबाइल क्रेचर फार वर्किंग मदर्स दिल्ली, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) कर-निर्धारित इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संयोजन पूर्णतया तथा अलग-अलग उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारित ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जैवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिताम के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9260/फा.सं. 197/34/93-आयकर (नि. 1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 1993

## (INCOME-TAX)

S.O. 146.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause 23-C of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Mobile Creches for Working Mother's Children New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1989-90 to 1991-92, subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9260/F. No. 197/34/93-ITA]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 147 :- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "मोबाइल क्रेचर फार वर्किंग मदर्स दिल्ली, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) कर-निर्धारित इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संयोजन पूर्णतया तथा अलग-अलग उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारित ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जैवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसे आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अधिव्यय के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार एक कर-निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राप्ति नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9261/फा.सं. 197/34/93-आयकर (नि.)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 147.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Mobile Creches for working Mother's Children, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment year 1992-93, subject to the following conditions, namely:—

- the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9261/F. No. 197/34/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

(आयकर)

फा.सं. 148.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्री राम कृष्ण आश्रम, पश्चिम बंगाल" को कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत रहने हुए एक उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- कर-निर्धारित इकाई आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संवयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- कर-निर्धारित उपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संयत पृथक् शर्तों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसे एक अथवा एक से अधिक हों अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जिस-र-जमाविला, फंडींग, आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक संग्रहण से प्राप्त) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- यह अधिसूचना किसी ऐसे आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अधिव्यय के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार एक कर-निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राप्ति नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9265/फा.सं. 197/61/93-आयकर (नि. -1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 31st March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 148.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Ramakrishna Ashram, West Bengal" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 to 1994-95, subject to the following conditions, namely:—

- the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9265/F. No. 197/61/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

(आयकर)

फा.सं. 149.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्री रामचन्द्र मिशन" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक के लिए एक उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 9278/फा.सं. 197/99/85-आयकर (नि.-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 7th May, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 149.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Ram Chandra Mission" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1985-86 to 1989-90.

[Notification No. 9278/F. No. 197/99/85-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

(आयकर)

फा.सं. 150.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्री रामचन्द्र मिशन" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहने हुए एक उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- कर-निर्धारित इकाई आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संवयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

- (ii) कर-निर्धारितो ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किताबें एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारितो के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9279/फा. सं. 197/99/86-आयकर  
(नि.—I)]

शरत चन्द्र, अवसर सचिव

New Delhi, the 7th May, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 150.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Ram Chandra Mission" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely:—

- the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9279/F. No. 197/99/86-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मई, 1993

(आयकर)

का.आ. 151.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (IV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट, बंबई" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- कर-निर्धारितो इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका

संचयन पूर्णतया तथा अतन्वयता उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

- कर-निर्धारितो ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारितो के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9282/फा.सं. 197/126/91-आयकर  
(नि.—I)]

शरत चन्द्र, अवसर सचिव

New Delhi, the 10th May, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 151.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sir Dorabji Tata Trust, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely:

- the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9282/F. No. 197/126/91-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मई, 1993

(आयकर)

क.आ. 152.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (IV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, बंबई" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-90 के लिए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 9284/फा. सं. 197/12/89-आयकर  
(नि.—I)]

शरत चन्द्र, अवसर सचिव

New Delhi, the 11th May, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 152.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "National Centre for performing Arts, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment year 1989-90.

[Notification No. 9284/F. No. 197/12/89-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मई, 1993

(आयकर)

का.आ. 153.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "हरियाणा अमलगायटेड फंड फॉर दि वेल्फेयर ऑफ एक्स सर्विस मैन" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक के लिए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 9285/का. सं. 197/106/91-आयकर  
(नि.—I)]

शरत चन्द्र, प्रवर सचिव

New Delhi, the 12th May, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 153.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Haryana Amalgamated Fund for the Welfare of Ex-servicemen" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1985-96 to 1989-90.

[Notification No. 285/F. No. 197/106/91-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मई, 1993

(आयकर)

का.आ. 154.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एण्ड मनेजमेंट सोसाइटी, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिणी ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से निम्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात,

कर्त्तृपर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से निम्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिवृद्धि के रूप में हो जब तक की ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-गुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9286/का. सं. 197/108/92-आयकर  
(नि.—I)]

शरत चन्द्र, प्रवर सचिव

New Delhi, the 12th May, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 154.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Dayanand Anglo-Vedic College Trust and Management Society, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely:

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9286/F. No. 197/108/92-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मई, 1993

(आयकर)

का.आ. 155.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "केरल आर्टीजन्स एण्ड स्किल्ड वर्कर्स (डेयकम रिटायर्मेंट) बेनीफिट स्कीम, बर्कलो" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिये इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिये करेगा, जिनके लिये इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनि, दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (ज्वर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा,

(iii) यह अभिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. : 9288/फा.सं. 197/49/93-आयकर (नि.-I)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 12th May, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 155.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Kerala Artisans and Skilled Workers (Death-cum-Retirement) Benefit Scheme, Quilon" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1989-90 to 1991-92 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9288/F. No. 197/49/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मई, 1993

(आयकर)

का.आ. 156.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा "गुरुदेव सिद्ध पीठ, महाराष्ट्र" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिये

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिये इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिये करेगा जिनके लिये इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिदिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (ज्वर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा।

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9289/फा.सं. 197/76/93-आयकर (नि.-I)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 12th May, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 156.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Gurudev Siddha Peeth, Maharashtra" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9289/F. No. 197/76/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मई, 1993

(आय-कर)

वा.पा. 157.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्री कैलाश आश्रम महासंस्थान ट्रस्ट, बंगलोर" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिये इसका संतान पूर्णतया अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिये करेगा, जिनके लिये इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिणी ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जबर-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9291/का.सं. 197/110/92-आयकर  
(नि.-I)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 17th May, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 157.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Kailash Ashram Mahasamsthan Trust, Bangalore" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in subsection (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless

the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9291/F. No. 157/110/92-ITA-II]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मई, 1993

(आय-कर)

वा.पा. 158.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "संजय गान्धी स्मॉलिंग ट्रस्ट, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (1) कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिये इसका संतान पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिये करेगा, जिनके लिये इसकी स्थापना की गई है;
- (2) कर-निर्धारिणी ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जबर-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9292/का.सं. 197/78/93-आयकर  
(नि.-I)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 17th May, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 158.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sanjay Gandhi Memorial Trust, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and

maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9292/F. No. 197/78/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मई, 1993

(आय कर)

का.आ. 159.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "गुजरात राज्य राहत समिति, अहमदाबाद" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिये उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 9293/फा.सं. 197/43/93-आय कर  
(वि.-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 17th May, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 159.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Gujarat Rajya Rahat Samiti, Ahmedabad" for the purpose of the said sub-clause for the assessment year 1989-90.

[Notification No. 9293/F. No. 197/43/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मई, 1993

(आयकर)

का.आ. 160.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "सेवा मन्दिर, उदयपुर, राजस्थान" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिता इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिये इसका संव्ययन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिये करेगा, जिनके लिये इसकी स्थापना की गई है ;

- (ii) कर-निर्धारिता ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5)

में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जैवर-जमाहूरत, फर्निचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वीकृत व्ययों से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा प्रभिताम के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिता के उद्देश्यों को प्राप्त के लिये प्राथमिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9297/फा.सं. 197/87/89-आयकर  
(वि.-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 28th May, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 160.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Seva Mandir Udaipur, Rajasthan" for the purpose of the said sub-clause for the assessment year, 1989-90 to 1991-92 subject to the following conditions namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9297/F. No. 197/87/89-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जून, 1993

(आयकर)

का.आ. 161.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "मध्य प्रदेश महिला कल्याण समिति, भोपाल" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :

- (i) कर-निर्धारिता इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिये इसका

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिये करेगा, जिनके लिये इसकी स्थापना की गई है;

- (2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (ज्वेल-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा।

- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अमिताभ के रूप में हो जब कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9302/फा. सं. 197/79/  
93-आय कर (नि.-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 8th June, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 161.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Madhya Pradesh Mahila Kalyan Samiti, Govind-pura, Bhopal" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- this notification will not apply in relation to any income bring profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9302/F. No. 197/79/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जून, 1993

(आयकर)

का.आ. 162:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "दि मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी, कालीकट" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1989-90 तक के लिये उक्त उपखंड के प्रयोगार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 9303/फा.सं. 197/139/  
89-आयकर (नि.-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 11th June 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 162.—In exercise of the powers conferred by sub-section (iv) clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Muslim Educational Society, Calicut" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1988-89 to 1989-90.

[Notification No. 9303/F. No. 197/139/89-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जून, 1993

(आयकर)

का.आ. 163.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी, कालीकट" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रखा हुआ उक्त उपखंड के प्रयोगार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात:—

- कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (ज्वेल-जवाहिरात फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अमिताभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखे पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9304/फा.सं.197/139/89-आयकर नि-1]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 11th June, 1993

## (INCOME-TAX)

S.O. 163.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Muslim Educational Society, Calicut" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9304/F. No. 197/139/89-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy

नई दिल्ली, 15 जून, 1993

(आयकर)

का.आ. 164 .—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "मिशनरीज ऑफ चैरिटी, कलकत्ता" को कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (1) कर-निर्धारिनी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अतन्वयतया उन उद्देश्यों के लिए किए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है।
- (2) कर-निर्धारिनी ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जबर-जबारागत फर्तीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के

संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9306/फा.सं.197/38/93-आयकर(नि-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 15th June, 1993

## (INCOME TAX)

S.O. 164.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Missionaries of Charity, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9306/F. No. 197/38/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 1993

(आयकर)

का.आ. 165 .—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि जे.आर.डी. टाटा ट्रस्ट, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (1) कर-निर्धारिनी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अतन्वयतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (2) कर-निर्धारिनी ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जबर-जबारागत, फर्तीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा,
- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा

कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9308/फा. सं. 197/111/91-आयकर (नि-1)]

शरत चन्द्र, अवसर सचिव

New Delhi, the 15th June, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 165.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The J.R.D. Tata Trust, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9308/F. No. 197/111/91-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 1993

(आयकर)

का.आ. 166.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, अमृतसर" को करनिर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (1) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (3) कर-निर्धारिती उपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर, वाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रखरखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9309/फा. सं. 197/87/93-आयकर (नि-1)]

शरत चन्द्र, अवसर सचिव

New Delhi, the 15th June, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 166.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Jallianwala Bagh National Memorial Trust, Amritsar" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 to 1994-95 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9309/F. No. 197/87/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 1993

(आयकर)

का.आ. 167.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "तमिलनाडु एक्स सर्विस पर्सनेल बनीवोलेण्ट फण्ड, मद्रास" को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (2) कर-निर्धारिती उपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी

एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (ज्वर-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9310/फा.सं. 197/41/93-आयकर-नि-1]  
शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 15th June, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 167.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Tamil Nadu Ex-services Personnel Benevolent Fund, Madras" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business

[Notification No. 9310/F. No. 197/41/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जून, 1993

(आयकर)

का.आ. 168.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्रीसिद्ध गंगा मठ, कर्नाटक" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संवयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती उपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (ज्वर-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9313/फा. सं. 197/116/91-आयकर-नि-1]  
शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 16th June, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 168.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sree Siddaganga Mutt, Karnataka" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9313/F. No. 197/116/91-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जून, 1993

(आयकर)

का.आ. 169.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "दहेज निवारण एवं सकान कल्याण परिषद्, इटावा उत्तर प्रदेश" को छोड़कर कर निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए संवयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (ज्वेयर-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्य तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं 9315/फा. सं. 197/89/93-आयकर (नि-1)]

शरत चन्द्र, अवसर सचिव

New Delhi, the 23rd June, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 169.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Dahej Niwaran Awam Samaj Kalyan Parishad, Etawah, Uttar Pradesh" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 to 1994-95 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9315/F. No. 197/89-93-ITA-1]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जून, 93

(आयकर)

का. आ. 170.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड, वेलफेयर, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1989-90 तक के लिए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 9316 फा. सं. 197/99/93-आयकर नि-1]

शरत चन्द्र, अवसर सचिव

New Delhi, the 23rd June, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 170.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indian Council for Child Welfare, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1988-89 to 1989-90.

[Notification No. 9316/F. No. 197/99/93-ITA-1]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जून, 1993

(आयकर)

का. आ. 171.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "एफ. आई. ई. फाउंडेशन, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)" को कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रखते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्—

(1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसका स्थान पता की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (ज्वेयर-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9318/फा. सं. 197/35/93-आयकर नि.-1]

शरत चन्द्र, अवसर सचिव

New Delhi, the 29th June, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 171.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "HIE Foundation, Kolhapur (Maharashtra)" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 to 1994-95 subject to the following conditions, namely:—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9318/F. No. 197/35/93-JTA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जून, 1993

(आयकर)

का. आ. 172 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्ततया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसका स्थापना की गई है।
- (2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं./9320/फा.सं. 197/100/93-आयकर नि. 1]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 29th June, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 172.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies “Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi” for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9320/F. No. 197/100/93-JTA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 जून, 1993

(आयकर)

का. आ. 173 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड iv द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “राम कृष्ण मिशन, बेलूर, पश्चिम बंगाल” को कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्ततया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9322/फा.सं. 197/82/93-आयकर (नि. 1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 29th June, 1993

## (INCOME-TAX)

S.O. 173.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Rama Krishna Mission, Belur, West Bengal" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1994-95 to 1996-97 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9322/F. No. 197/82/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 1993

(आयकर)

का. आ. 174 —आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "रमण केन्द्र, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (2) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (ज्वेल-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9323/फा.सं. 197/170/88-आयकर(नि. 1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 30th June, 1993

## (INCOME-TAX)

S.O. 174.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Ramana Kendra, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1989-90 to 1991-92 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9323/F. No. 197/170/88-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1993

(आयकर)

का. आ. 175 :—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "सोसायटी फॉर सोशल फोरे-स्ट्री रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट तमिलनाडु" को कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (ज्वेल-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त

तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9327/फा. सं. 197/115/93—आयकर (नि. 1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 7th July, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 175.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Society for Social Forestry Research & Development, Tamil Nadu" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 to 1994-95 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9327/F. No. 197/115/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1993

( आयकर )

का. आ. 176 :—आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "नेशनल इस्टीमेट्स आफ बैंक मैनेजमेंट, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक के लिए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 9328/फा. सं. 197/124/87—आयकर नि.-1]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 7th July, 1993  
(INCOME-TAX)

S.O. 176.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "National Institute of Bank Management, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1987-88 to 1989-90.

[Notification No. 9328/F. No. 197/124/87-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1993

( आयकर )

का. आ. 177 :—आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "नादर महाजन संगम, मदुरै," को कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक के लिए निम्न-लिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (1) कर निर्धारिती इसकी आय का हस्तमाल अथवा इसकी आय का हस्तमाल करने के लिए इसका सचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (2) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्षों वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों में इसकी निधि (जेवर-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9333/फा. सं. 197/111/93—आयकर नि.-1]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 9th July, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 177.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Nadar Mahajana Sangam, Madurai" for the purpose

of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 to 1994-95 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. F. No. 197/111/93-ITAI]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1993

( आयकर )

का. आ. 178 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “सीफर्स वेलफेयर एंड सोसाइटी, बम्बई” को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए, इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की, की भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों, से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहरात फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में प्रत्येक गे लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9333/फा. सं. 197/67/93—आयकर  
नि. 1]  
शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 9th July. 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 178.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies “Seafarers’ Welfare Fund Society, Bombay” for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. F. No. 197/67/93-ITAI]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1993

(आयकर)

का. आ. 179 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “लिटल मिस्टर्स आफ दि पृथ्वी, कलकत्ता” को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों की संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहरात फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो-

वार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं ही रखी जानी हों।

[अधिसूचना सं. 9335/फा. सं. 197/125/93-आयकर नि-1]  
शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 9th July, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 179.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Little Sisters of the Poor, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9335/F. No. 197/125/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1993

(आयकर)

का. आ. 180.—आयकर अधिनियम, 1961- (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा (जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, अमृतसर) को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिता इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिता ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा II की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वीकृत अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त-कर-निर्धारिता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रारम्भिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जानी हों।

[अधिसूचना सं. 9338/फा. सं. 197/87/93-आयकर नि.-1]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 9th July, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 180.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Jallianwala Bagh National Memorial Trust, Amritsar" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1989-90 to 1991-92 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9338/F. No. 197/87/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

(आयकर)

का. आ. 181.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार हैंडी-क्राफ्ट्स, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिता इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिता ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा II की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा

तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेयर-जवाहिरात, फनीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान में भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारितो के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9342/फा. सं. 197/134/93-आयकर-नि-1]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 26th July, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 181.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9342/F. No. 197/134/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1993

(आयकर)

का. आ. 182.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "दि आगा खां फाउंडेशन, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारित इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के

लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

- (ii) कर-निर्धारितो उक्त उद्देशित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्वांश वर्षों की कियों भी प्रयोजन के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेयर-जवाहिरात, फनीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान में भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारितो के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना संख्या 9343/फा. सं. 197/29/93-आयकर-  
(नि.-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 26th July, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 182.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Aga Khan Foundation, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9343/F. No. 197/29/93-ITA-II]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1993

(आयकर)

का. आ. 183.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "कृष्णमूर्ति फाउंडेशन आफ इंडिया, मद्रास"

को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसकी संचयन पूर्णतया अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जबकि जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ।
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलयभ के रूप में जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो ।

[अधिसूचना सं. 9347/फा. सं. 197/73/93-आयकर (नि-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 6th August, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 183.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Krishnamurti Foundation of India, Madras" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9347/F. No. 197/73/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1993

(आयकर)

का. आ. 184.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "राजीव गांधी फाउंडेशन, "जनरल फण्ड", नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जबकि जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9352/फा. सं. 197/113/91-आयकर (नि-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 12th August, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 184.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Rajiv Gandhi Foundation 'General Fund' New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 to 1994-95 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant

to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;

- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9352/F. No. 197/113/91-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1993

(आयकर)

का.आ. 185.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "दि केरल टोड्डी वर्क्स वेलफेयर फंड बोर्ड, त्रिवेन्द्रम" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के लिए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं० 9354/फा.सं. 197/193/91-आयकर नि० I]  
शरत चन्द्र, अपर सचिव

New Delhi, the 17th August, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 185.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Kerala Toddy Workers Welfare Fund Board, Trivandrum" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[Notification No. 9354/F. No. 197/193/91-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1993

(आयकर)

का.आ. 186.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "स्वामी रामानन्द तीर्थ मॉरियल कमेटी, हैदराबाद" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

- (2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववत् वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनि-

दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक हेतु अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरान, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा।

- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं० 9357/फा.सं/197/108/93-आयकर (नि-1)]  
शरत चन्द्र, अपर सचिव

New Delhi, the 25th August, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 186.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Swami Ramananda Tritha Memorial Committee" Hyderabad for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9357/F. No. 197/108/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1993

(आयकर)

का.आ. 187.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्रीमन्म साई सेंट्रल, बंगलूर" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए

करेगा, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है;

- (2) कर-निर्धारिता ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा तर्कों में भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जबर-जवाहिरान, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ तथा अभिलाष के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9359/फा.सं. 197/80/93-आयकर  
(नि.-1)]  
शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 26th August, 1993  
(INCOME-TAX)

S.O. 187.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Sathya Sai Central Trust, Bangalore" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9359/F. No. 197/80/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

(आयकर)

का.आ. 188.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा "एसोसिएशन आफ मेडीकल फिजीसिस्ट्स आफ इंडिया बॉम्बे" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 में 1991-

92 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहने हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है. अर्थात्:—

- (1) कर-निर्धारिता इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका मंचयन पूरनगा तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (2) कर-निर्धारिता ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 2 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा तर्कों में भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जबर-जवाहिरान, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा जमा नहीं करवा सकेगा;
- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ तथा अभिलाष के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9364/फा.सं. 197/45 93-आयकर  
(नि.-1)]  
शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 9th September, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 188.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Association of Medical Physicists of India, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1989-90 to 1991-92 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9364/F. No. 197/45/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

(आयकर)

का.आ. 189.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “सर्व सेवा संघ, वर्धा” को कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों में भिन्न तरीकों में इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान में भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9365/फा.सं. 197/128/93-आयकर-  
(नि.-I)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 19th September, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 189.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies “Sarva Seva Sangh, Wardha” for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9365/F. No. 197/128/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1993

(आयकर)

का.आ. 190.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “जहांगीर आर्ट गैलरी, बंबई” को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों में भिन्न तरीकों में इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान में भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9366/फा.सं. 197/131/93-आयकर(नि.-I)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 9th September, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 190.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies “Jehangir Art Gallery, Bombay” for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9366/F. No. 197/131/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 सितंबर, 1993

(आयकर)

का.आ. 191.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा "एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फिजीसियन्स ऑफ इंडिया बंबई" को कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(ii) कर-निर्धारिती उपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों के संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में यात्रा में लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9367/फा.सं. 197/45/93-आयकर(नि-I)]

शरत चन्द्रा, अवसर सचिव

New Delhi, the 9th September, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 191.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Association of Medical Physicists of India, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 to 1994-95 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9367/F. No. 197/45/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1993

(आयकर)

का.आ. 192.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "महाराष्ट्र स्टेट व्हेमस काउंसिल, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;

(ii) कर-निर्धारिती उपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों के संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में यात्रा में लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9376/फा.सं. 197/92/93-आयकर (नि-I)]

शरत चन्द्रा, अवसर सचिव

New Delhi, the 23rd September, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 192.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Maharashtra State Women's Council, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9376/F. No. 197/92/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1993

(आयकर)

आ. 193.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "महाराष्ट्र महिला परिषद्, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिता इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इस का संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिता ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिता के उद्देश्यों की

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9384/का.सं. 197/42/93-आ.कर (वि-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 1st October, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 193.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Oil Coordination Committee, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9384/F. No. 197/42/93-ITA-I]  
SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1993

(आयकर)

आ. 194.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्रीमती प्रबन्ध संस्थान, आनन्द, गुजरात" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिता इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिता ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9386/फा.सं. 197/163/90-प्रा.कर (नि-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 4th October, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 194.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Institute of Rural Management, Anand, Gujarat" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9386/F. No. 197/163/90-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1993

(आयकर)

फा. आ. 195.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "इण्डियन एक्स मैनेजमेन्ट लीग, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संस्थान पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के

3 GI/94—6

दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा ग्दर-ग्दराव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;

- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9387/फा.सं. 197/140/93-प्रा.कर (नि-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 4th October, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 195.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indian Ex-services League, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9387/F. No. 197/140/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1993

(आयकर)

फा. आ. 196.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उपखण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "पश्चिम बंगाल मुख्य मंत्री राहत कोष, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से

1991-92 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते  
उक्त उपखण्ड के प्रयोजार्थ अधिसूचित करती, अर्थात्—

- (i) कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिन्हें लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिणी ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंगदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9390/फा.सं. 197/145/93-प्रा.कर(नि-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 1993

#### (INCOME-TAX)

S.O. 196.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "West Bengal Chief Minister's Relief Fund, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1989-90 to 1991-92 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9390/F. No. 197/145/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1993

(आयकर)

का. आ. 197.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-1) के उपखण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "पश्चिम बंगाल मुख्य मंत्री राहत कोष, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1993-94 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्—

- (i) कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिन्हें लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिणी ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंगदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9391/फा.सं. 197/145/93-प्रा.कर(नि-1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 1993

#### (INCOME-TAX)

S.O. 197.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "West Bengal Chief Minister's Relief Fund, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1992-93 to 1993-94 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and

maintained in the form of jewellery, furniture etc. for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

- (ii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9391/F. No. 197/145/93-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 नवंबर, 1993

(आयकर)

का. आ. 193.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "से इन्वेंट्रियुअर आफ रेल ट्रांसपोर्ट, नई दिल्ली" का कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वक्षान रहने हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करता है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसका अर्थ का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिसे लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर-निर्धारिणी उपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जैवरजवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंगदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिणी के उद्देश्यों का प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेख-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9395/फा. सं. 197/172/91-आ. कर (नि-1)]

New Delhi, the 2nd November, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 198.—in exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Institute of Rail Transport, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9395/F. No. 197/172/91-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 नवंबर, 1993

(आयकर)

का.आ. 199.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "से रेल ट्रांसपोर्ट, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वक्षान रहने हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिणी इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसका अर्थ का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिसे लिए इसकी स्थापना की गई है ;
- (ii) कर निर्धारिणी उपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जैवरजवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंगदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिणी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेख-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

[अधिसूचना सं. 9398/फा. सं. 197/61/90-आयकर (नि-1)]

शरत चन्द्र, अधर सचिव

शरत चन्द्र, अधर सचिव

New Delhi, the 4th November, 1993

## (INCOME-TAX)

S.O. 199.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23-C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sir Ratan Tata Trust, Bombay" for the purpose of the sub clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established ;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewelery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11 ;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9398/F. No. 197/61/90-ITA-I]

SHANTI CHANDRA Under Secy.

नई दिल्ली, 24 दिसंबर, 1993

का.आ. 200.—केन्द्र सरकार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 3 के खंड (ड) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध को प्रवृत्त करने के प्रयोजनार्थ श्री ए. पी. काला को प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त करती है, जिनका पदाभिधान विशेष प्रवर्तन निदेशक होगा और उक्त अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्हें तख्तीन बनाए गए किसी नियम, निदेश या आदेश या उसके उपबंधों में से किसी भी उपबंध [धारा 13, धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (क), धारा 18क और धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) से भिन्न] के उल्लंघन के मामलों का अधिनियम करने के लिए सशक्त करती है।

[फा. सं. 174/2/93-तक.सम. (प्र.)]

एस. ए. हुड्डा, निदेशक

New Delhi, the 24th December, 1993

S.O. 200.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, read with clause (2) of section 3 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Central Government hereby appoints Shri A. P. Kala to be an officer of Enforcement with the designation of Special Director of Enforcement for the purpose of enforcing the provisions of the said Act; and in exercise of the powers conferred by section 50 of the said Act hereby empowers him to adjudicate cases of contravention of any of the provisions, thereof [other than section 13, clause (a) of sub-section (1) of section 18, section 18A and clause (a) of sub-section (1) of section 19 or of any rule, direction or order made thereunder.

[F. No. 174/2/93-TC(E)]

S. A. HUDA, Director

(आर्थिक कार्य विभाग)

बीमा प्रभाग

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1993

का.आ. 201.—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (1956 का 31) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री जे. एम. मालुके, प्रबंध निदेशक, को एतद्वारा एक जनवरी, 1994 से 31 जुलाई 1996 तक, जो कि उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख है, भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा. सं. 14(4)/93-बीमा-5]

सी. एस. राव, संयुक्त सचिव

(Department of Economic Affairs)

INSURANCE DIVISION

New Delhi, the 17th December, 1993

S.O. 201.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri J. S. Salunkhe, Managing Director as The Chairman of the Life Insurance Corporation of India with effect from 1st January, 1994 upto 31st July, 1996 i.e. the date of his superannuation.

[F. No. 14(4)/93-Ins.V]

C. S. RAO, Jt. Secy.

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसंबर, 1993

का.आ. 202.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय के तत्कालीन राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के दिनांक 13-2-1991 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस. ओ. 97 (ई) में निम्नांकित संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना में "गंजम जिला" शब्दों के स्थान पर "गंजम और गजपती जिले", शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

[सं. एक 1/1/93-प्रार. वार. बी.]

सी. बी. प्रसाद, अवसर सचिव

(Banking Division)

New Delhi, the 27th December, 1993

S.O. 202.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in the erstwhile Department of Revenue and Banking of Ministry of Finance, vide No. S.O. 97(E), dated 13th February, 1991, namely :—

In the said notification, for words "district of Ganjam" the words "districts of Ganjam and Gajapati", shall be substituted.

[No. F. 1/1/93-RRB]

C. B. PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 दिसंबर, 1993

का. आ. 203.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय के तत्कालीन राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के दिनांक 11-11-1976 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस ओ 726 (ई) में निम्नांकित संशोधन करती है, नामतः—  
उक्त अधिसूचना में “कोरापुट जिला” के स्थान पर “कोरापुट, मल्कागिरी, नवरंगपुर एवं रायगढ़ जिले”, शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

[सं. एफ 1(1)/93-आर.आर.वी.]

सी. बी. प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 27th December, 1993

S.O. 203.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in the erstwhile Department of Revenue and Banking of Ministry of Finance, vide No. S.O. 726(E), dated the 11th November, 1976, namely:—

In the said notification for the words “district of Koraput”, the words “districts of Koraput, Malkangiri, Nowrangpur and Rayagada”, shall be substituted.

[No. F. 1(1)/93-RRB.]

C. B. PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1993

का. आ. 204.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 5 के उपखण्ड (1), खण्ड 7 और खण्ड 8 के उपखण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात्, एतद्वारा देना बैंक के वर्तमान कार्यपालक निदेशक श्री के. कन्नन को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 9/34/93-वी.ओ.-I]

एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 29th December, 1993

S.O. 204.—In pursuance of sub-rule (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 5, clause 7 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri K. Kannan, presently Executive Director of the Dena Bank, as the Chairman and Managing Director of the Dena Bank for a period of five years commencing with the date of his taking charge.

[F. No. 9/34/93-B.O.I.]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समन्वयक

अधिसूचना सं. 11/1993

नागपुर, 14 दिसंबर, 1993

का.आ. 205.—श्रीमती एम. एम. सोनम, लेखा परीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह “ख” समाहृतलय नागपुर निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-11-1993 को अपराह्न से शासकीय सेवा से निवृत्त हुए हैं।

[सं. 11(3)/14/93/स्थापना-1/26284]

हरजिंदर सिंह, उपायुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता)

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

NOTIFICATION NO. 11/1993

Nagpur the 14th December, 1993

S.O. 205.—Smt. M. M Sonam, Examiner of Accounts, Central Excise Group ‘B’ of Nagpur Collectorate having attained the age of superannuation retired from Government service on 30-11-1993 in the Afternoon.

[C. No. II(3)/14/93/Estt.1/26284]

HARJINDER SINGH, Dy Collector (Per. and Vig.)

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसंबर, 1993

का. आ. 206.—मै. ड्यूक फैगनस (प्रा.) लिमिटेड सुधियाना को ई पी सी जी योजना के अंतर्गत संलग्न सूची के अनुसार पूंजीगत माल के आयात के लिए 16,17,366/- रु. (सोलह लाख पन्द्रह हजार तीन सौ छयासठ रुपये) आयात लाइसेंस सं. पी/सी जी/2131274 दिनांक 8-1-1993 मंजूर किया गया था।

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क तथा विनियम नियंत्रण प्रयोजन की दूसरी प्रतिलिपियां हम आधार पर जारी करने के लिए आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क तथा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां खो गई हैं अथवा गुम हो गई हैं। यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क तथा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत नहीं कराई गई थी तथा इस प्रकार सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का विलकुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक तिरुपुर के समक्ष विधिवत शपथ लेकर स्टम्प पेपर पर एक हलफनामा दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूँ कि फर्म से आयात लाइसेंस सं. पी/सी जी/213274 दिनांक 8-11-93 की मूल सीमाशुल्क तथा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां खो गई हैं या गुम हो गई हैं। समय-समय पर यथासंशोधित

आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 को उप-धारा 9 (ग) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै. ड्यूक फैशन्स (प्रा.) लिमिटेड, लुधियाना को जारी की गई उक्त मूल सीमाशुल्क तथा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति सं. पी/सी.जी./2131274, दिनांक 8-11-93 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

3. पार्टी को उक्त लाइसेंस की दूरी सीमाशुल्क तथा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं।

[फा. सं. 18/एम 94/37/ई पी सी जा-2/400]

माया डी. केम, उप महा निदेशक,  
विदेश व्यापार

### MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

#### ORDER

New Delhi, the 23rd December, 1993

S.O. 206.—M/s. Duke Fashions (Pvt.) Ltd, Ludhiana were granted and Import licence No. P/CG/2131274, dated 8-11-93 for Rs. 16,17,366 (Rupees sixteen lakhs seventeen thousand three hundred and sixty six) import of CG as per list enclosed under EPCG Scheme.

The firm has applied for issue of Duplicate copies of Custom and Exchange Control purpose of the above mentioned licence on the ground that the original Custom and Exchange Control purpose copies of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Custom and Exchange Control purpose copies of the licence were not registered with any Customs Authority and as such the value of customs purpose copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary public Tirpur. I am accordingly satisfied that the original Customs and Exchange Control purpose copies of Import licence No. P/CG/2131274 dt. 8-11-93 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955, dt. 7-12-1955 as amended the said original Custom and Exchange Control purpose copy No. P/CG/2131274 dt. 8-11-93 issued to M/s. Duke Fashions (Pvt.) Ltd., Ludhiana is hereby cancelled.

3. A duplicate Custom and Exchange Control purpose copies of the said licence is being issued to the party separately.

[F. No. 18/AM 94/787/EPCG-II/400]

MAYA D. KEM, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

(विदेश व्यापार महा निदेशाज्ञा)

आदेश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1993

कां.आ. 207.—मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि० एनटीपीसी स्क्वायर, 62-69, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कैपिटल गुड्स-400 केवी जनरेटर ट्रांसफार्मर पैकेज

के आयात के लिये 2,67,56,985- रुपए (दो करोड़ सड़सठ लाख छप्पन हजार, नौ सौ पचासी रुपये मात्र) का आयात लाइसेंस सं० जी०एच० 2044774, दिनांक 6-3-89 दिया गया था।

2. फर्म से मूल आयात लाइसेंस (सीमाशुल्क प्रयोजन) विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। मैं संतुष्ट हूँ कि फर्म से मूल आयात लाइसेंस सं० जी एच 2044774, दिनांक 6-3-1989 खो गया है। अतः यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 को उप-धारा 9 (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि०, एनटीपीसी स्क्वायर, 62-69, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को जारी की गई उक्त मूल आयात लाइसेंस (सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति) विनिमय नियंत्रण प्रति सं० जी एच 2044774, दिनांक 6-3-1989 एतद्वारा रद्द की जाती है।

3. पार्टी को आयात लाइसेंस सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुति अलग से जारी की जा रही है।

[एफ० सं० सीजीआई/एचईपी/30/88-89/225]

श्रीमती रीता माथुर, उप महा निदेशक

(Directorate General of Foreign Trade)

#### ORDER

New Delhi, the 29th December, 1993

S.O. 207.—M/s. National Thermal Power Corporation Ltd., NTPC Square, 62-69, Nehru Place, New Delhi-110019 were granted Import Licence No. GH/2044774, dated 6-3-89 for Rs. 2,67,56,985 (Rupees Two Crore Sixty Seven Lakhs Fifty Six Thousand Nine Hundred and Eighty Five only) for import of Capital Goods 400 KV Generator Transformer Package against Reserve Bank of India Guidelines.

2. The Original Import Licence (Custom Purpose)/Exchange Control Copy has been misplaced by the firm. I am satisfied that the Original Import Licence No. GH/2044774, dated 6-3-1989 has been misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(CC) of the Import (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended the said Original Import Licence (Custom Purposes Copy) Exchange Control Copy No. GH/2044774, dated 6-3-1989 issued to M/s. National Thermal Power Corporation Ltd., NTPC Square, 62-69, Nehru Place, New Delhi, is hereby cancelled.

3. A duplicate Import Licence Custom Purposes Copy/Exchange Control Copy is being issued to the party separately.

[F. No. CGI/HEP/30/88-89/225]

SMT. RITA MATHUR, Dy. Director General

## नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक

वितरण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1993

का.आ. 208.—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा श्री एन.एस. चौधरी को लेफ्टिनेंट जनरल ए.एस. भुल्लर, जिन्होंने 23 दिसम्बर, 1993 (अपराह्न) को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, के स्थान पर इसी समय से भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करती है। श्री चौधरी की नियुक्ति उनकी 60 वर्ष की आयु होने तक पुनर्नियुक्ति आधार पर होगी। श्री चौधरी का वेतन सरकारी नियमों/प्रादेशों, जैसे कि उन पर लागू होते हैं, द्वारा शासित होगा।

[मिसिल सं. 1/6/93-बी.आई.एस.]

ए.एल. माखीजानी, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS

AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 23rd December, 1993

S.O. 208.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby appoints Shri N. S. Choudhary as Director-General of the Bureau of Indian Standards with immediate effect vice Lt. Genl. A. S. Bhullar who completes his tenure on 23rd December, 1993 (AN). The appointment of Shri Choudhary shall be on re-employment basis till he attains the age of 60 years. The pay of Shri Choudhary will be governed by the Govt. of India rules/orders as applicable to him.

[File No. 1/6/93-RIS]

A. L. MAKHIJANI, Under Secy.

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1993

का.आ. 209.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बढबली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 24 अगस्त, 1990 में प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की अधिवृत्ता का.आ. सं. 2352, तारीख 24 अगस्त, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य रैंक का अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी

नियुक्त करती है और यह भी निदेश देती है कि उक्त संपदा अधिकारी, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों की वास्तव अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थायी सीमाएं

(1)

(2)

मुख्य महा प्रबंधक, चण्डीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ जिले की राजस्व सीमा के भीतर स्थित चण्डीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के सभी स्थान अथवा उसके द्वारा या उसकी ओर से गृह पर किए गए या उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी स्थान।
---	--

[फा.सं. 18(4)/90-एस.एस.आई.(पं.)]

बेनी राम, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries)

New Delhi, the 30th December, 1993

S.O. 209.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Industry, S.O. No. 2352, dated the 24th August, 1990, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 24th August, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being equivalent in rank to a gazetted officer of Government, to be estate officer for the purposes of the said Act, and further directs that the said estate officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act, within the limits of his jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table, namely:—

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Chief General Manager, Chandigarh Industrial and Tourism Development Corporation Limited, Chandigarh.	All premises belonging to, or taken on lease by, or on behalf of or under the administrative control of, the Chandigarh Industrial and Tourism Development Corporation Limited situated within the revenue limit of Chandigarh District.

[F. No. 18(4)/90 - SSI(P)]

BENI RAM, Under Secy.

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1993

पूर्ण विश्वास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के मामले में

राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के मामले में

का. भा. 210.—राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किए गए प्रारम्भ पर और उनकी सहमति से पूर्ण विश्वास अधिनियम 1890 (1890 का 6) के खण्ड 10(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ए. ब. द्वारा आदेश देती है कि तत्पश्चात् नए बचत के अनुसार रु. 8,73,937 (अठ्ठा लाख शताब्द हजार नौ सौ पैंतीस मात्र) सिडिकेट बैंक, कृष्ण नगर, नई दिल्ली में 46 दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट योजना के अन्तर्गत 7% की व्याज दर से 30-10-93 को निवेश की गई।

क्रम सं.	राशि	निवेश का तारीख	मुदत का तारीख	अतिरिक्त
1.	रु. 5,63,553/-	12-09-93	28-10-93	
2.	रु. 3,10,384/-	--	--	रुको बैंक, शाहपुरजट, नई दिल्ली में जमा 1.25 करोड़ की बचत हुई राशि।

2. भारत सरकार के तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के दिनांक 2 मार्च, 1979 के समय-समय पर यथा संशोधित सां. भा. 120(ई) की अधिसूचना के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के संचालन की योजना के अनुसार प्रयोग किए जाने हेतु उक्त योजना द्वारा भारतीय पूर्ण विश्वास योजनाओं के नाम होता।

[सं. 13-4/93-डी-आर-II]  
सुरजित लाल, अधीक्षक

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Women &amp; Child Development)

New Delhi, the 17th December, 1993

## IN THE MATTER OF THE CHARITABLE ENDOWMENTS ACT, 1890 (6 of 1890)

## IN THE MATTER OF THE NATIONAL CHILDREN'S FUND, NEW DELHI

S.O. 210.—On the application made by and with the concurrence of the Board of Management of the National Children's Fund, New Delhi and in exercise of the powers conferred by Section 10(2) of the Charitable Endowments Act 1890 (6 of 1890), the Central Government do hereby order that the sum of Rs. 8,73,937/- (Rupees Eight Lakh Seventythree Thousand nine hundred and thirtyseven only) as per particulars given below be re-invested in Fixed Deposit

Scheme for 46 days in Syndicate Bank, Hauz Khas, New Delhi at the rate of interest 7% per annum w.e.f. 30-10-1993:—

Sl. No.	Amount	Date of previous Investment	Date of Maturity	Remarks
1.	Rs. 5,63,553/-	12-09-93	28-10-93	
2.	Rs. 3,10,384/-	--	--	Balance amount of discounted value of Rs. 1.12 crores invested with UCO Bank, Shahpurjat, New Delhi.

2. The above account shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments of India to be held by him for being applied in accordance with the scheme for the administration of the National Children's Fund, New Delhi published with the Notification of the Government of India in the then Department of Social Welfare No. S.O. 120 (E) dated the 2nd March, 1979 as amended from time to time.

[F. No. 13-4/93 TR-II]

SURJIT LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1993

का. भा. 211.—राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किए गए प्रारम्भ पर और उनकी सहमति से पूर्ण विश्वास अधिनियम 1890 (1890 का 6) के खण्ड 10(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ए. ब. द्वारा आदेश देती है कि तत्पश्चात् नए बचत के अनुसार रु. 63,06,306/- (छह लाख छ. हजार नौ सौ छ. मात्र) (रु. 70,00,000/- छूट कमी की राशि) इंडिया बैंक, सहरजटा एनक्लेव, नई दिल्ली में एक वर्ष के लिए सिडिकेट बैंक डिपॉजिट योजना के अन्तर्गत 11% की व्याज दर से 9-11-93 को पुनः निवेश की गई।

क्रम सं.	राशि	निवेश का तारीख	मुदत का तारीख	अतिरिक्त
1.	रु. 65,00,000/-	7-08-93	7-11-93	बचत हुई राशि राष्ट्रीय बाल कोष के बचत खाते में जमा कराई जायेगी।

2. भारत सरकार के तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के दिनांक 2 मार्च, 1979 के समय-समय पर यथा संशोधित सां. भा. 120(ई) की अधिसूचना के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के संचालन की योजना के अनुसार प्रयोग किए जाने हेतु उक्त योजना द्वारा भारतीय पूर्ण विश्वास योजनाओं के नाम होता।

[सं. 13-4/93-डी-आर-II]

सुरजित लाल, अधीक्षक

New Delhi, the 17th December, 1993

S.O. 211—On the application made by and with the concurrence of the Board of Management of the National Children's Fund, New Delhi and in exercise of the powers conferred by Section 10(2) of the Charitable Endowments Act 1890 (6 of 1890), the Central Government do hereby order that the sum of Rs. 63,06,306/- Rupees Sixtyth-ree Lakh Six thousand three hundred and six only) (discounted value of Rs. 70,00,000/-) as per particulars given below be re-intested in Certificate of Deposit Scheme for one year in Indian Bank, Sudarjung Enclave, New Delhi at the rate of interest 11% per annum w.e.f. 09-11-1993.

Sl. No.	Amount	Date of previous Investment	Date of Maturity	Remarks
1.	Rs. 65,00,000/-	07-08-93	07-11-93	Balance amount will be deposited in Saving Bank Account of NCF.

2. The above account shall vest in the Treasurer of Charitable endowments of India to be held by him for being applied in accordance with the scheme for the administration of the National Children's Fund, New Delhi published with the Notification of the Government of India in the then Department of Social Welfare No. S.O. 120 (E) dated the 2nd March, 1979 as amended from time to time.

[F. No. 13-4/93 TR-II]  
SURJIT LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1993

कां० आ० 212.—राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के प्रबन्ध बां द्वारा किए गये और उनके सहमति से पूर्व विन्यास अधिनियम 1890 (6 of 1890) के खंड 10(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एवम् द्वारा आदेश देते हैं कि नीचे दिए गए ध्योरे के अनुसार रु. 1,21,89,616/- (एक करोड़ दसकोस लाख नवसो हजार छ सौ पचास मात्र) रु. 1,35,00,000/- छूट कीमत का राशि) स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया नए गाँवा, राजियाबाद में एक वर्ष के लिए सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉजिट योजना के दरवा 10.75% का ब्याज दर से 30-10-93 को पुनः निवेश की गई।

क्रम सं. : दि. : निम्न निवेश भुगतान की अधिवृत्ति  
तारीख तारीख

1.	रु. 1,25,00,000/-	31-07-93	30-10-93	यहां हुई राशि सिजिकेट बैंक हाउस खात, नई दिल्ली में 46 दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट योजना में जमा कराई गई।
----	-------------------	----------	----------	---

2. भारत सरकार के तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के दिनांक 2 मार्च, 1979 के समय-समय पर यथा संशोधित सं. आ. 120(ई) का 3 GI/94—7

अधिसूचना के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के मंचालन की योजना के अनुसार प्रयोग किए जाने हेतु उक्त खाता भारतीय पूर्व विन्यास के खर्जाओं के नाम होगा।

[सं. 13-4/93-टी-आर-II]

सुरजित लाल, सचिव

New Delhi, the 17th December, 1993

S.O. 212.—On the application made by and with the concurrence of the Board of Management of the National Children's Fund, New Delhi and in exercise of the powers conferred by Section 10(2) of the Charitable Endowments Act 1870 (6 of 1870), the Central Government do hereby order that the sum of Rs. 1,21,89,616/- (Rupees one Crore Twentyone Lakh eighty nine thousand and six hundred sixteen only) (discounted value of Rs. 1.35 crores) as per particulars given below be re-invested in Certificate of Deposit Scheme for one year in State Bank of Patiala, Surya Nagar Ghaziabad, at the rate of interest 10.75% per annum w.e.f. 30-10-1993.

Sl. No.	Amount	Date of previous Investment	Date of Maturity	Remarks
1.	Rs. 1,25,00,000/-	31-07-93	30-10-79	Surplus amount be deposited in FD for 46 days in Syndicate Bank, Hauz Khas, New Delhi.

2. The above account shall vest in the Treasurer of Charitable endowments of India to be held by him for being applied in accordance with the scheme for the administration of the National Children's Fund, New Delhi published with the Notification of the Government of India in the then Department of Social Welfare No. S.O. 120 (E) dated the 2nd March, 1979 as amended from time to time.

[F. No. 13-4/93 TR-II]  
SURJIT LAL, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1993

कां० आ० 213.—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय आयु-विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में और हिमाचल प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् डा० बी०के० भार्गव, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, इन्दिरा गांधी आयुविज्ञान महाविद्यालय को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से भारतीय आयुविज्ञान परिषद का सदस्य नाम निर्दिष्ट किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० कां० आ०

138 (संख्या 5-13 : 59-एम आई) तारीख 9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नाम निविष्ट "शीर्षक के नीचे क्रम संख्यांक 21 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"21. डा० वी०के० भार्गव,  
निदेशक, चिकित्सा शिक्षा,  
इन्दिरा गांधी आर्युर्विज्ञान महाविद्यालय,  
शिमला।"

[सं० वी 11013/11/93-एम ई (यूजी)]

अमरजीत सिंह, उप सचिव

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th December, 1993

S.O. 213.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) the Central Government in consultation with the Government of Himachal Pradesh, have nominated Dr. V. K. Bhargava, Director, Medical Education, Indira Gandhi Medical College to be member of the Medical Council of India with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health. No. S.O. 138 (No. 5-13/59-MI), dated the 9th January, 1960 namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (a) of sub-section (1) of section 3" for serial number 21 and the entry relating thereto the following serial number and entry shall be substituted, namely :—  
"21.

Dr. V. K. Bhargava,  
Director Medical Education,  
Indira Gandhi Medical College,  
Shimla."

[No. V-11013/11/93-ME(UGE)]

AMARJIT SINGH, Dy. Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1993

का. आ. 214:—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का एक) की धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री मीर नमकुल्लाह को 25-10-93 के बाद दिल्ली नगर कला आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्हें तीन वर्ष की और कार्य-कालावधि होने के निर्णय तक कार्य करने रहने का अनुमोदन करती है।

[सं. ए-11013/4/83-डी. डी. वी / बी.VI/1 बी/ 1 ए]

आर० देनर्जी, निदेशक

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

New Delhi, the 19th November, 1993

S.O. 214.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (one of 1974), the Central Government hereby approves the continuance of Shri Mir Nasrullah as Chairman, Delhi Urban Art Commission after 25-10-1993 till a view is taken for giving him a fresh three years term.

[No. A-11013/4/83-DDVB/VI/IB/IA]

R. BANNERJI, Director

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का. आ. 215:—केन्द्रीय सरकार का, दिल्ली मुख्य योजना/सेवरीय(डिवीजनल) विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में, यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लॉक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम एवं पता भी अवश्य दे।

संशोधन :

"योजना डिवीजन "एफ" उप जोन एफ-8 (ओखला) में पड़ने वाले और दक्षिण में रेलवे क्वार्टरों से, पश्चिम में सी. सी. आई. प्राईडिंग इकाई से, उत्तर में डी. टी. सी. कम्पाउंड वाल से और पूर्व में मथुरा आगरा रेलवे लाइन से घिरे 39 हेक्टेयर (96.33 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "महानगर यात्री टर्मिनल (23.7 हेक्टेयर) जिला पार्क (9.8 हेक्टेयर) समाज सदन (2.1 हेक्टेयर) और मुख्य योजना मार्ग (परिवहन) (3.4 हेक्टेयर)" से "भांडागार और डिपो (आई. सी. डी.)" में इस शर्त पर बदलने का प्रस्ताव है कि ले-आउट प्लान में दर्शाए गए 39 हेक्टेयर में से 6 हेक्टेयर (14.82 एकड़) क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में रखा जाए और उसका रख-रखाव किया जाए।"

2. प्रस्तावित संशोधन की दशति वाला नक्शा निराकरण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में उपनिदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ-3 (41)/89—एम. पी.]

वी. एम. बंसल, आयुक्त एवं सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 215.—The following modification, which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal (Divisional) Development Plan for Delhi, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objections/suggestions in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objections/suggestions should also give his name and address.

"The land use of an area, measuring 39 ha. (96.33 acres) falling in Planning Division 'F' sub-zone F-8 (Okhla) and bounded by Railway quarters in the South, CCI grinding unit in the West, DTC compound wall in the North and Mathura Agra Railway Line in the East, is proposed to be changed from 'Metropolitan Passenger Terminal (23.7 ha.) District Parks (9.8 ha.) Community Centre (2.1 ha.) and Master Plan Road (Transportation) (3.4 ha.)' to 'Warehousing and Depots (ICD)' subject to that 6 ha. (14.82 acres) to be retained and maintained as green out of 39 ha. as shown in layout plan."

2. The plan indicating the proposed modification, will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi, on all working days within the period referred above.

[No. F. 23(41)/89-MP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum Secy.

## सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का. आ. 216 :—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में, यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति अथवा सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लॉक, आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दे। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

संशोधन :

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड-3, उपखंड (2) के पृष्ठ 121 पर निम्नलिखित व्यवस्था है :—

भूमि उपयोग	भूमि की %
आवासीय	45-55
व्यावसायिक	3-4
औद्योगिक	6-7
मनोरंजनात्मक	15-20
सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	
सुविधाएं	8-10
परिचालन	10-12

इसे निम्नलिखितानुसार बदलने का प्रस्ताव है :—

भूमि उपयोग	भूमि की %
आवासीय	48-58
व्यावसायिक	5-6 (2% सेवा उद्योग के लिए)
मनोरंजनात्मक	15-20
सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	
सुविधाएं	10-12
परिचालन	10-12

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में उप-निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ-20 (19)/93-एम. पी.]

वी. एम. बंसल, आयुक्त एवं सचिव

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st December, 1993.

S.O. 216.—The following modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi 2001. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi within a period of 30 days from the date of this notice. The person making objections/suggestions should also give his name and address.

## MODIFICATIONS :

At page 121 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1-8-90 which reads as follows :

Land Use	% of Land
Residential	45-55
Commercial	3-4
Industrial	6-7
Recreational	15-20
Public & Semi public facilities	8-10
Circulation	10-12

is proposed to be replaced by the following as under :

Land Use	% of Land
Residential	48-58
Commercial	5-6 (2% of for service industry)
Recreational	15-20
Public and Semi public facilities	10-12
Circulation	10-12

2. The proposed modification will be available for inspection in the office of the Deputy Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi on all working days during the period referred above.

[No. F. 20(19)/93-MP]

V.M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

## सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1994

का.आ. 217.—दिल्ली विकास (मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 5 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 10 (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने तथा उसके प्रकाशन के लिए सूचना।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:—

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जोन एक (दक्षिणी दिल्ली-1) के लिए एक क्षेत्रीय विकास योजना प्रारूप तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, भूतल, विकास मीनार में भेजा जा रहा है 3 में उल्लिखित तारीख तक सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध होगी।

2. इस प्रारूप योजना के सम्बन्ध में एतद्वारा आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

3. आपत्ति एवं सुझाव लिखित रूप में आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास सदन, नई दिल्ली-23 को सन् 1994 के फरवरी, महीने की 13 तारीख से पहले भेजें।

आपत्ति/सुझाव भेजने वाले व्यक्ति को अपना नाम नाम एवं पता भी अवश्य देना चाहिए।

[फाइल सं. एफ-1(22)/92—जैड.पी.]

विश्व मोहन बंसल,  
आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY  
PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 5th January, 1994

S.O. 217.—Notice under Section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rule 5 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, of the preparation and publication of the draft of the Zonal Development Plan for the National Capital Territory of Delhi.

Notice is hereby given that :

- A draft of a Zonal Development Plan for Zone 'F' (South Delhi-I) in the National Capital Territory of Delhi has been prepared.
- A copy thereof will be available for inspection of the office of the Delhi Development Authority on Ground floor, Vikas Minar between hours, of 11 A.M. to 5 P.M. on all working days till the date mentioned in para 3 hereinafter.

2. Objection and suggestions are hereby invited with respect to this draft plan.

3. The objection or suggestion may be sent in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, New Delhi-23 before the 13th day of February, 1994.

Any person making the objection or suggestion should also give his name and address.

NEW DELHI

Dated 15-1-94.

[F. No. F. 1(122)/92-ZP]

V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

## संचार मंत्रालय

## (दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1993

का. आ. 218.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 29 के उपनियम (1) के खण्ड (vi) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि:—

दूरसंचार विभाग में कार्यरत किसी सरकारी कर्मचारी के लिए यदि अपील प्राधिकारी, विभाग में मुख्य महाप्रबंधक नहीं हैं वहां महाप्रबंधक (पदनाम प्राधिकारी के अधीनस्थ स्तर का है, तो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक को, जैसा भी मामला हो, नियम 29 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से संशोधन का प्राधिकारी होगा।

[सं. 12-2/88-विजी. III]

श्रीमती गार्गी मुखर्जी, निदेशक

(डी ई एंड वी पी)

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 28th December, 1993

S.O. 218.—In exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub-rule (1) of Rule 29 of the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby specifies that:—

in the case of a Government servant serving in the Department of Telecommunications for whom the appellate authority is subordinate to the authority designated as Chief General Manager/General Manager (whereat here is no Chief General Manager) in the Department, the Chief General Manager/General Manager as the case may be shall be a revising authority for the purpose of exercising the powers under rule 29.

[No. 12-2/88-Vlg. III]

MRS. GARGI MUKHERJEE, Director (DE&VP)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1994

का. आ. 219.—चूंकि भारतीय तार नियमावली 1951 के नियम 434 (iii) (2) (ग) के अनुसार देहरादून तथा क्लेमेंट टाउन टेलीफोन एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र में संशोधन करने के बारे में देहरादून तथा क्लेमेंट टाउन में प्रचलित समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें सम्भावित: इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की आपत्तियां तथा उनके सुझाव समाचारपत्रों में सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर मांगे गए थे ;

और चूंकि उपर्युक्त सूचना "अमर उजाला" में 12-1-93 और "दैनिक जन लहर" तथा "दून दर्पण" समाचारपत्रों में 15-1-93 को प्रकाशित की गई थी ;

और चूंकि उपर्युक्त सूचना के उत्तर में जनता से कई आपत्तियां तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब उपर्युक्त नियमावली के नियम 434 (iii) (2) (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 16-1-94 से देहरादून का संशोधित स्थानीय क्षेत्र इस प्रकार होगा ;

देहरादून टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

देहरादून टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में देहरादून नगरपालिका देहरादून छावनी बोर्ड तथा क्लेमेंट टाउन टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि. मी. की भरीय दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र शामिल होंगे, बशर्ते कि जो टेलीफोन उपभोक्ता देहरादून नगरपालिका तथा छावनी बोर्ड की सीमा से बाहर रहते हों लेकिन जिन्हें देहरादून टेलीफोन प्रणाली द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है, वे तब तक स्थानीय शुल्कों का भुगतान करते रहेंगे जब तक (क) वे इस प्रणाली के किसी भी एक्सचेंज की 5 कि. मी. की भरीय दूरी के भीतर रहते हों, और (ख) इस तथ्य के बावजूद कि वे किसी निकटवर्ती टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत आते हुए भी, विभागीय कारणों से इससे जुड़े रहते हैं।

[फा.सं. 3—7/85—पीएचबी]

गुरदीप सिंह, निदेशक

New Delhi, the 7th January, 1994

S.O. 219.—Whereas a public notice for revising the local area of Dehradun and Clement Town Telephone Exchange Systems was published as required by rule 434(III)(2)(c) of the Indian Telegraph Rules, 1951, in the Newspapers in circulation at Dehradun and Clement Town inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby,

within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 13-1-1993 in 'Amar Ujala' and on 15-1-1993 in 'Dainik Jan Labar' and 'Door Darpan' newspapers;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 434(III)(2)(c) of the said Rules, the Director General Telecommunications hereby declares that with effect from 16-1-94, the revised local area of Dehradun shall be as under :—

Dehradun Telephone Exchange System

The local area of Dehradun Telephone System shall cover the areas falling under the jurisdiction of Dehradun Municipality, Dehradun Cantonment Board and the areas within 5 kms radial distance from Clement Town Telephone Exchange;

Provided that the telephone subscribers located outside Dehradun Municipality and Cantonment Board limits but who are served from Dehradun Telephone System shall continue to pay local tariffs as long as (a) they are within 5kms radial distance of any exchange of this system and (b) remain connected to it due to departmental reasons notwithstanding the fact that they may fall within the local area of any adjacent telephone systems.

[F. No. 3-7/85-PHB]

GURDIP SINGH, Director (Phones-E)

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1993

का.आ. 220.—अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 की उपधारा (3) और खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, श्री के. एन. अर्धनारीश्वरन अध्यक्ष, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सदस्य, भारत अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड को 28-6-1993 (अपराह्न) से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31-12-1993 तक उनके अपने कार्यभार के अलावा भारत अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का भार संभालने के लिये नियुक्त करती है।

[संख्या ए वी 24011/05/93 वी ई ]

एच. ए. संधु, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 24th November, 1993

S.O. 220.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and clause (6) of Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri K. N. Ardhanareeswaran, Chairman, National Airports Authority (NAA) and Member on the Board of the International Airports Authority of India (IAAI) to hold additional charge of the post of Chairman, IAAI, in addition to his own duties w.e.f. 28-6-1993 (A/N) to 31-12-1993, the date of his superannuation.

[No. AV. 24011/05/93-VE]

H. S. SANDHU, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1993

का.प्र. 221.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, एफसीआई के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-42012/24/87 डी II (बी) डी IV (बी)]

राजा लाल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 17th December, 1993

S.O. 221.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workmen, which was received by the Central Government on 15-12-93.

[No. L-42012/24/87-D.II(B)D-IV(B)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT

HYDERABAD

Present :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated : 30th day of November, 1993

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 15 OF 1992

BETWEEN

G. Gannamma

.. Petitioner

AND

1. The Senior Regional Manager,

F.C.I., Hyderabad.

2. District Manager, F.C.I.,

Srikakulam.

3. Assistant Depot Manager,

F.C.I., Amadalavalasa.

.. Respondents.

Appearances :

M/s. V. Sudhakar Reddy & G. Ramesh, Advocate for  
the Petitioner.

Sri Koka Satyanarayana Rao, Advocates for Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-42012(24)/87-D.II.B/D.IV(B), dt. 17-2-1992 referred the following dispute under Section 10(1)(d) (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of Food Corpo-

ration of India Srikakulam and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of District Manager, Food Corporation of India, Srikakulam retrenching Smt. G. Gannamma, Part-time Sweeper without following the provisions of I. D. Act, 1947 is justified ? If not to what relief Smt. Gannamma is entitled ?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 15 of 1992 and notices were served on both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner-workman read as follows : The Workman claimant submit that she was appointed as a Sweeper by the 3rd Respondent Management by his order dated 5-12-1979. From time to time the 2nd Respondent Management enhanced her salary and she was paid a salary of Rs. 150.00 per month. She was also paid bonus at 8.33 per cent till the year 1984-85. She worked for more than 6 years continuously the entire satisfaction of her superiors. As the claimant happened to be a poor Harijan with large family and the salary paid to her was meagre. She demanded the management from time to time for the enhancement of salary and for regularisation. The 2nd Respondent-Management by his order dt. 1-5-1986 for the reasons best known to him, terminated the services of the claimant with retrospective effect from 30-4-1986. The claimant was neither paid one month salary nor served with one month notice before termination. The termination order is also served by the 3rd Respondent-Management on 3-5-1986 to the claimant. No terminated benefits were paid to claimant. An insufficient amount as terminal benefits are paid to the claimant, when she claimed the action of the management as illegal. Out of poverty of the claimant, she received the draft dated 15-5-1986 for an amount of Rs. 463.55. The claimant respectfully submit that many of Sweepers were regularised in the organisation. The claimant respectfully submit that the action of the management in terminating the services of the workman as malafide besides being contrary to law. The management has contravened the provisions of the I. D. Act. Since the date of her termination, she was kept out of employment and she could not secure alternative employment elsewhere in spite of her repeated efforts. The claimant respectfully submit that even the insufficient amount is paid subsequent to her date of termination. She was neither served one month notice stating reasons nor paid wages in lieu thereof. Hence the action of the management in terminating the services of the claimant is illegal and in contravention of the provision of the I.D. Act. Therefore the claimant workman prays that the Hon'ble Tribunal may pleased to pass an order declaring the action of the management as illegal, null and void and direct the management to reinstate the workman with continuity of services and back wages.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent-Corporation read as follows : The allegation of the petitioner that the demand for reinstatement with continuity of the service is just and proper is not true and correct. The petitioner was appointed as a part time Sweeper @ Rs. 25.00 p.m. in the year 1979. The Petitioner's salary was increased to Rs. 100.00 w.e.f. 1-1-1982 and Rs. 150.00 p.m. w.e.f. 1-4-1982. The petitioner was paid Rs. 150.00 p.m. till the date the petitioner was retrenched from service. Since there was no work and hence the part-time sweepers were found surplus and therefore the services of the petitioner were retrenched w.e.f. 30-4-1986 A.N. The Petitioner was paid Rs. 463.55 towards one month's notice pay and 15 days wages for each year of service as per Sec. 25-F of I. D. Act. The petitioner accepted the notice pay and retrenchment compensation paid to her. The master and servant relationship came to an end as the petitioner accepted her terminal benefits. The allegation that the Petitioner demanded the management from time to time for enhancement of salary and for regularisation is totally false and incorrect. The allegation that the termination of the services of the Petitioner is malafide besides being contrary to law is totally false and incorrect. The petitioner service was terminated due to non-availability of work. It is also submitted that the Respondent i.e. Management also received circulars not to make any fresh appointment to the entry level posts of Cat. III & IV during the year 1985 consequent on ban imposed by the Central Government for entry level post. The allegation that the petitioner was neither served one month's notice nor paid wages in lieu thereof is not true and correct.

As already stated the petitioner was paid one month's notice pay and 15 days wages for each year of service. The action of the Management is neither illegal nor there is any contravention to the provisions of I. D. Act. In view of what has been stated above it is proved that this Hon'ble Tribunal may be pleased to reject the reference and pass a nil award.

4. The point for adjudication is whether the action of the Management of District Manager, F.C.I. Srikakulam in retrenching Smt. G. Gannamma Part-time sweeper without following the provisions of I. D. Act is justified or not ?

5. W.W1 and W.W2 were examined on behalf the Petitioner and marked Exs. W1 on its side. M.W1 and M.W2 were examined on behalf of the Respondent Management and marked Exs. M1 to M14 on its side.

6. W.W1 is G. Gannamma. She deposed that she worked as Sweeper and Safaewally with the Management. She used to sweep the office and also used to clean 6 latrines. She used to sweep the godowns also. She used to work from 7.00 a.m. to 6.00 p.m. She was working in the F.C.I. only. Junior workers, one Annapura Jaya Durga and one Sanyasamma and Lakshmi who were juniors to her in service were continued in service by the Management whereas she was terminated from service. The above said 4 persons were regularised in service. She was prevented from joining the service from 30-4-1989. She received the notice leave wage after 20 days through a demand draft. After her termination from service by the Management, she tried for some other job in different organisation but failed. She used to represent the management for enhancement of wages and also for regularising her. The workers union also took up her cause and demanded the management for regularising the service and also enhancing the wage. The termination order was furnished to her on 1-5-1986. As she was terminated illegally she filed this application for directing the management for reinstating her in service and also for back wages.

7. W.W2 is Bregu Jagaram. He deposed that he is working as Kalsi in F.C.I. Amadalavalasa Branch since 1971. They are having a labour contract Society there. The Society is doing the contract work of handling and transport of the bags relating to F.C.I. The Society is known as "Chilagam-Singavalasa labour Contract Cooperative Society. There is another Krishnapuram Labour Contract Society. These two Societies were now handling the work. He knows the petitioner. She was working F.C.I. since 1979. She was coming to the office by 6.30 a.m. or 7 a.m. She was cleaning the latrines, keeping water there, brooming the godowns verandas, watchman bunks and cabins. After 9.30 after the opening the godowns she was brooming inside. She was brooming the office room and keeping water there. She was working upto 6 or 7 P.M. During the season of 6 months the office will be opened around 6.30 or 7 A.M. and in unseason by 9.30 A.M. The petitioner was continuously working, one Annapura, Lakshmi, Jaya Durga and Gangasamma are working in the F.C.I. Their services are regularised. All of them are juniors to the Petitioner. After removal from service, the petitioner was approaching the Management for employment. Petitioner is illiterate.

8. M.W1 is Ch. Benerjee. He deposed in brief that he worked at SKL Dt. office from November, 1984 to April 1988, as Assistant Manager General. During that period he was looking the establishment and Administration. Annadalavalasa Depot is within the purview of SKL Dt. office. The petitioner was working as part time Sweeper in Amadalavalasa Depot, during the tenure of his office. Ex. M1 is the copy of the appointment order of the petitioner marked to Dt. Office. As per the order the petitioner worked at the rate of Rs. 25.00 per month. She was never on the regular pay roles of the office. The petitioner was retrenched as per the office order, marked under Ex. M2 w.e.f. 30-4-1986. She was retrenched as per the directions of the Regional office. Ex. M3 is the copy of the order of the Regional Office copy the policy proceedings of the head of the Management sent to Amadalavalasa Depot a cheque for Rs. 463.55 rs. for payment of retrenchment compensation to the petitioner. Ex. M4 is the forwarding letter Ex. M5 is the sanction order for arranging payment to the petitioner. The Amadalavalasa, manager, received it on 3rd May, 1986. The same is endorsed on Ex. by me. The AM of Amadalavalasa returned the amount to Dt. Office, along the forwarding letter Ex. M6, as the petitioner refused to receive the amount. Ex.

M7 is the voucher showing the crediting of the same amount in the F.C.I. Account. Then the Dt. Office purchased the D.D. and sent it to the petitioner by R.P. Ex. M8 is the office copy of the covering letter. The petitioner received it and Ex. M9 in the postal acknowledgement. As per the provisions they appointed D. Jayadurga, K. Lakshmi, G. Annapura and B. Sanyasamma under the dependent deceased quota. Ex. M10 is the true copy of the circular letter of the headquarters. As the petitioner refused to receive the compensation at the Amadalavalasa Depot, which necessitated to send the same by D.D. and which resulted in delay. She was appointed to sweep the office to keep some water for the staff members. She was expected to come the office by 9 a.m. and leave by 10 a.m. on working days. Beyond that her services were no longer received. The petitioner was never asked to scavenge the latrine.

9. M.W2 is A. Das Venkata Reddy. He deposed on brief that he worked at Amadalavalasa in the Respondent Corporation as Asst. Manager, Depot from 15th May, 1984 to 16th June, 1986. He knows the petitioner. She worked as part-time sweeper at Amadalavalasa branch of the Respondent. The nature of work assigned to a part-time sweeper are to sweep the office room and to provide water for the use of the staff members. The part-time sweeper should come to the office by 10.00 a.m. After completing the above said work the part time sweeper may go away. The Respondent was paying the wages to the petitioner from the office imprest money. The petitioner was retrenched w.e.f. 30th April, 1986. He received the office order retrenching the petitioner on 2-5-86. He received the said order through a special courier. The said order was immediately served on the petitioner on the very same day. Ex. M2 is the copy of the said order. For about a week her tendered the amount to the petitioner every day. He tried his best to give the compensation amount to the petitioner but she refused to receive.

10. In this dispute the petitioner workman stated that she was appointed as a Sweeper by an order of the Management dated 5th December, 1979 and the Management enhanced her salary from time to time and she was paid a monthly salary of Rs. 150.00 at the time of retrenchment. She was also paid bonus at the rate of 8.33 per cent. She continuously worked for more than 6 years. As the salary paid to her was meagre, she used to demand for the enhancement of the salary and for regularisation of her services. For the best known to the Management, terminated her services by its order dated 1st May, 1986 with retrospective effect w.e.f. 30th April, 1986.

11. On the other hand, the contention of the Respondent-Management is that the action of the management is legal and in accordance with the provisions of I.D. Act, the regular sweepers in South Zone were found excess than the sanctioned strength and as a result the services of the petitioner were terminated. The management further averred that an amount of Rs. 463.55 was paid to the claimant towards one month notice pay and 15 days wages for each year of service as per Sec. 15-F of the I.D. Act.

12. Now the Tribunal has to see whether the Management has complied with the provisions of Sections 25-F, 25-G and 25-H of the I.D. Act. In the present case the petitioner-workman herself was examined as W.W1 and another workman was examined as W.W2 to substantiate her case. On behalf of the Management two witnesses were examined as M.W1 and M.W2 and 14 documents were marked as Exs. M1 to M14.

13. As per the evidence of W.W1 and W.W2 the claimant used to work from 7 a.m. to 6 p.m. usually any sweeper should attend to her duties for one or one and a half hour prior to the other employees reach the office and they will leave only after 1 or 1-1/2 hour after the other staff leaves. The same is substantiated by their Lordships reported in S.C. L.J. (1950 to 1977) at page 1549. M.W1 also admitted about the working conditions. Even otherwise as per a decision reported in 1984 (49) FLR page 57 Kerala High Court held that person employed whether full time or part time is a workman under Section 2(a) of the I.D. Act. The management also admitted in its counter that they have complied

with the conditions laid down under Section 25-F of the I.D. Act which implies the claimant will come under the purview of Section 2(s) of the I.D. Act. It is an admitted fact that as per Ex. M2, the services of the petitioner-workman were terminated with effect from 30th April, 1986, whereas the compensation was paid after 12th May, 1986. The compensation (15 days wages) is to be paid by calculating on the basis of last drawn salary. But in this case insufficient amount was paid. As per the evidence of M.W1, and M.W2 as the petitioner refused to receive the amount the same was sent by way of D.D. Due to poverty the petitioner received the same. Even otherwise it will not amount waiver of her rights, in view of the circumstances of the case and as per catena of decisions one of which is reported in 1979 LIC page 1338 and 1977(1) LLJ page 94 (Madras High Court). As the benefit provided under Section 25-F of the I.D. Act which are conditions precedent for retrenchment, were not complied with, the order of termination is illegal and void ab initio, in view of catena of decisions of the Hon'ble Supreme Court and various High Courts. It is substantiated by a decision reported in 1981(II) LLJ page 70 S.C. Payment of insufficient amount is also violation of the conditions precedent. The same was upheld by their Lordships in a judgement reported in 1980(40) FLR (SC) page 474. Regarding the violation of Section 25-G of the I.D. Act that M.Ws. 1 and 2 admitted that Laxmi, Jayadurga, Sanyasamma and Annappurna are the Sweepers and are juniors to the claimant and their services have been subsequently were regularised. The Management also not prepared any seniority list as per Rule 77 of the I.D. (Central) Rules which is mandatory. As such the Management has violated the principle "Last Come First Go". In this case the juniors are retained while terminating the services of the petitioner-workman. As per the evidence of M.W.1 and M.W.2, the Management appointed fresh sweepers, subsequent to the termination of the services of the petitioner-workman. But at no time, the petitioner-workman has been given an opportunity for employment as provided under Section 25-H of the I.D. Act. In the counter, the management stating that there is no comparison with the regular sweepers but stated her services were terminated as regular sweepers found excess. At another place, stated that the services of the petitioner-workman were terminated as per the orders of the superiors. Even the management stated that her services are no longer required, subsequently the above mentioned sweepers were appointed. M.W.1 in the cross-examination admitted that Jayadurga, Sanyasamma, Laxmi and Annappurna were appointed later. M.W.1 admitted that the services of many casual and part-time sweepers are regularised in South Zone. The petitioner workman submits that it is denied in the counter about the fact of making representation by her. M.W1 and M.W2 admitted in the cross-examination that the claimant used to make representations for regularisation and for enhancement of salaries. As such with a mala fide intention the services of the petitioner-workman were terminated illegally. The petitioner-workman was requested to perform the duties of both sweeping and scavenging. As per the circular, the services of the scavengers cannot be terminated. To prove the fact of performance of duties of scavenging, issued a notice for the production of the impress register R.E. If vouchers and cash book MW1 also admitted that the said fact will be revealed by going through the Impress Register. To prove the fact of timings, the petitioner workman issued a notice for the production of the Muster. But the Respondent conveniently avoided to produce the same. Being a custodian, the Respondent is supposed to produce the said documents. Having taking into consideration of the above facts, I find that the management failed to comply with the provisions of Sections 4-F, 25-G and 25-H of the I.D. Act.

14. In the result, the action of the Management of District Manager, Food Corporation of India, Srikakulam, in retrenching Smt. G. Gannamma, Part-time Sweeper without following the provisions of I.D. Act is not justified. The Petitioner-workman is entitled to be reinstated into service with full back wages and continuity of service and with all attendant benefits.

15. Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 30th day of 1994.

Y. VENKATACHAIAM, Industrial Tribunal-I

## Appendix of Evidence

### Witnesses Examined

for Workmen:

W.W1 G. Gannamma

W.W2 R. Jayaram

### Witnesses Examined for Management :

M.W.1 Ch. Bononjee

M.W.2 A. Dasvenkataratnam

### Documents marked for the Workmen:

Ex. W1/9-3-90—Office Order issued by F.C.I., Zonal Office, Madras.

### Documents marked for the Management:

Ex. M1/5-12-79—Appointment later of the petitioner.

Ex. M2/1-5-86—Termination letter of the petitioner.

Ex. M3/10-7-85—Letter to D.M./FCINSP by Regl. Office FCI, Hyderabad regarding regularisation of Part Time Sweeper.

Ex. M4/3-5-86—Letter addressed to Asst. Manager, FCI, Amadalavalasa by District Office, FCI/Skl. regarding retrenchment compensation of the petitioner.

Ex. M5/1-5-86—Payment voucher for Rs. 463.55.

Ex. M6/12-5-86—Letter addressed to OM/FCI/Skl by Asst. Manager, FCI, Amadalavalasa.

Ex. M7/13-5-86—Payment voucher for Rs. 463.55.

Ex. M8/16-5-86—D.D. for Rs. 463.55 covering letter.

Ex. M9—Postal acknowledgement.

Ex. M10/14-4-87—Circular issued by Deputy Manager (Projects) FCI/New Delhi regarding terminal benefits.

Ex. M11/20-12-82—Office order issued FCI/Skl. regarding appointment of D. Jaya Durga.

Ex. M12—Appointment letter of K. Laxmi.

Ex. M13/22-1-87—Appointment order of G. Annappurna.

Ex. M14/24-2-86—Appointment order of B. Sanyasamma.

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1993

का.प्रा. 222—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुबन्ध में, केन्द्रीय सरकार, आई.एफ.सी.आई. के प्रबन्धन के संवद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/221/91 आई प्रार (बी2)]

एस.एस.के. राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th December, 1993

S.O. 222.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of I.F.C.I. and their workmen, which was received by the Central Government on 16-12-93.

[No. L-12012/221/91-IR(B-II)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI

I.D. No. 146/91

In the matter of dispute between :

Shri Mange Ram through Mahasachiv, Akhil Bhartiya  
Udyogic Vit Nigam Karamchhari Sangh, 12th Floor,  
Bank of Baroda Bhawan, 16, Sansad Marg, New  
Delhi-110001.

Versus

Maha Prabandhak (Prashasan), Industrial Finance Cor-  
poration of India, Bank of Baroda Bhawan, 16,  
Sansad Marg, New Delhi-110001

## APPEARANCES :

None—for the workman.

Shri P. K. Mehra—for the Management.

## AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide  
its Order No. 12012/221/91-IRBII dated 22-11-91 has re-  
ferred the following industrial dispute to this Tribunal for  
adjudication:

"Whether the action of the management of Industrial  
Finance Corporation of India in not giving bene-  
fits of Pro-rata Increment to Shri Mange Ram, Peon-  
cum-Chowkidar as per circular No. 17/88 dated  
20-4-88 is justified? If not, to what relief is the  
workman entitled to?"

2. In this case Miss Meenakshi had been appearing on  
behalf of the workman but nobody appeared in this case on  
behalf of the workman for four dates continuously. The  
workman was proceeded against ex parte and the manage-  
ment also did not lead any evidence. In view of  
the fact that the workman has not filed any document nor  
contested the dispute it appears that no dispute exist be-  
tween the parties. I, therefore, order that a no dispute  
award be given in this case leaving the parties to bear their  
own costs.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

10th November, 1993.

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1993

का.आ. 223—औद्योगिक विवाद अधिनियम,  
1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में  
केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम लि. के प्रबंध-  
तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच,  
अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार  
औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित  
करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-12-1993 को  
प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-17012/05/90 आई आर (बी-2)]

एस.एस.के. राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th December, 1993

S.O. 223.—In pursuance of Section 17 of the Industrial  
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government  
hereby publishes the Award of the Central Government In-  
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in  
3 GI/94—8.

the industrial dispute between the employers in relation to  
the management of LIC of India and their workmen, which  
was received by the Central Government on 16-12-93.

[No. L-17012/05/90-IR(B-II)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI

I.D. No. 70/90

In the matter of dispute between :

Shri Raj Kumar S/o Shri Baljit, C/o Delhi Labour  
Union, Aggarwal Bhawan, G.T. Road, Tis Hazari,  
Delhi-110054.

Versus

The Manager, Life Insurance Corporation of India, 25,  
Kasturba Gandhi Marg, New Delhi

## APPEARANCES :

Shri C. P. Aggarwal—for the workman.

None—for the Management.

## AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide  
its Order No. L-17012/5/90-I.R.B-I dated 12-7-90 has re-  
ferred the following industrial dispute to this Tribunal for  
adjudication :

"Whether the action of the Management of LIC of  
India, New Delhi in terminating the services of  
Shri Raj Kumar, Safai Karamchhari w.e.f. 1-12-88  
is justified? If not to what relief the workman is  
entitled to?"

2. The representative for the workman Shri C. P. Aggar-  
wal made statement that the workman was not interested  
to pursue the matter a No dispute award may be given in  
this case. In view of this statement of the representative  
No dispute award is passed in this case leaving the parties  
to bear their own costs.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

2nd November, 1993.

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1993

का.आ. 224—औद्योगिक विवाद अधिनियम,  
1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में,  
केन्द्रीय सरकार, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के प्रबंधतंत्र के  
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबन्ध में  
निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक  
अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो  
केन्द्रीय सरकार को 16-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/222/92 आई आर (बी-2)]

एस. एस. के. राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th December, 1993

S.O. 224.—In pursuance of Section 17 of the Industrial  
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government  
hereby publishes the Award of the Central Government In-  
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in  
the industrial dispute between the employers in relation to  
the management of Punjab & Sind Bank and their workmen,  
which was received by the Central Government on 16-12-93.

[No. L-12012/222/92 IR(B-II)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI  
I.D. No. 99/92

In the matter of dispute between .

Smt. Kailash, through Joint Secretary, Punjab and Sind  
Bank Staff Federation (Regd.), Flat No 73, Plot  
No. 12, Sector 14, Sheetal Apartment, Rohini,  
Delhi-110085.

Versus

Deputy General Manager (CE), Punjab & Sind Bank,  
C-14/16, Atma Ram House, Connaught Place,  
New Delhi.

## APPEARANCES :

None—for the workman.

Shri Lajwinder Singh—for the Management.

## AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide  
its Order No. L-12012/222/92 IRB-II dated 30-10-92 has  
referred the following industrial dispute to this Tribunal for  
adjudication :

"Whether the action of the management of Punjab &  
Sind Bank not providing proper scale and benefits  
to Smt. Kailash from last 12 years is justified? If  
not to what relief is the workman entitled?"

2. The workman was proceeded ex parte in this case on  
4-10-93. None had appeared on behalf of workman. Even  
on 16-8-93. On 12-11-93 the management made a state-  
ment that they will consider the posting of the claimant at  
any new branch. In view of the fact that the workman has  
produced no evidence and has been proceeded against ex-  
parte and even in ex parte statement management has assured  
that in case of any vacancy they would adjust the work-  
man against the said job. No dispute award is passed in  
this case leaving the parties to bear their own costs.  
November 15, 1993.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1993

का.प्रा. 225—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947  
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय  
सरकार, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के प्रबंधतंत्र के संबंध नियो-  
जकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट  
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण  
नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय  
सरकार को 16-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/221/92-आई आर (बी-2)]

एस.एस.के. राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th December, 1993

S.O. 225.—In pursuance of Section 17 of the Industrial  
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government  
hereby publishes the Award of the Central Government In-  
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure to  
the industrial dispute between the employers in relation to  
the management of Punjab & Sind Bank and their workmen.  
which was received by the Central Government on 16-12-93.

[No. L-12012/221/92-IR(B-II)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFI-  
CER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI-  
BUNAL : NEW DELHI

I.D. No. 98/92

In the matter of dispute between :

Smt. Krishna through  
Joint Secretary,  
Punjab & Sind Bank Staff Federation.  
Flat No. 73, Sector-14,  
Sheetal Apartments,  
Rohini, Delhi-110085.

Versus

The Deputy General Manager (CZ),  
Punjab & Sind Bank,  
C-14/16, Atma Ram House,  
Connaught Circus, New Delhi.

## APPEARANCES :

None for the workman.

Shri Lajwinder Singh for the Management.

## AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide  
its Order No. L-12012/221/92 IR B-II dated 30-10-92 has  
referred the following industrial dispute to this Tribunal for  
adjudication :—

"Whether the action of the management of Punjab &  
Sind Bank not providing proper scale and benefits  
to Smt. Kailash from last 12 years is justified? If  
not, to what relief is the workman entitled?"

2. The workman was proceeded ex parte in this case on  
4-10-93. None has appeared on her behalf even on 16-8-93.  
On 12-11-93 the management made statement that they will  
consider the posting of the claimant at any new branch. In  
view of the fact that the workman has produced no evi-  
dence and has been proceeded ex parte and even in ex parte  
statement management has assured that in case of any  
vacancy they would adjust the workman against the said  
job. No dispute award is passed in this case leaving the parties  
to bear their own costs.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

November 15, 1993

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1993

का.प्रा. 226—औद्योगिक विवाद अधिनियम,  
1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में  
केन्द्रीय सरकार, सिडीकट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबंध नियो,  
जकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट  
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण,  
नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय  
सरकार को 16-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/75/91-आई आर (बी-2)]

एस.एस.के. राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th December, 1993

S.O. 226.—In pursuance of Section 17 of the Industrial  
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government  
hereby publishes the Award of the Central Government In-  
dustrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in  
the industrial dispute between the employers in relation to  
the management of Syndicate Bank and their workman which  
was received by the Central Government on 16-12-93.

[No. L-12012/75/91-IR(B-II)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI

I. D. No. 95/91

In the matter of dispute between :  
Smt. Kamla Devi through  
Zonal Secretary,  
Syndicate Bank Staff Association,  
Ram Naresh Bhawan,  
Tilak Gali,  
Paharganj, New Delhi.

Versus

The Manager,  
Syndicate Bank,  
Sarojini House,  
6, Bhagwan Dass Road, New Delhi.

APPEARANCES :

None.

## AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/75/91-IR-B-2 dated nil has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of Syndicate Bank, Zonal Office, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi not treating Smt. Kamla Devi part time sweeper as regular full time sweeper though working for 39 hours per week and sweeping and wet mopping an area of 4350 Square feet daily as per appointment letter dated 20-7-88 was justified ? If not to what relief the workman is entitled to ?"

2. Management evidence was recorded in this case and the case was fixed for workman evidence. He was directed to file affidavit but he neither filed affidavit nor appeared her self. It appears that the workman was not interested in pursuing the dispute. On the basis of the evidence produced on record by the management his witness having been fully cross-examined by the workman representative. I find no dispute exist between the parties and, therefore, pass a no dispute award in this case.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer  
November 10, 1993

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1993

का.आ. 227.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, कानारा बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-12-93 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-12011/116/87-डी-2(ए)]

एस.एस.क. राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th December, 1993

S.O. 227.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal Madras as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Canara Bank

and their workmen which was received by the Central Government on 20-12-93.

[No. L-12011/116/87-DIIA]

S. S. K. RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU,  
MADRAS

Thursday, the 2nd day of December, 1993

PRESENT :

Thiru K. Sampath Kumaran, B.A.B.L.,  
Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 43/1988

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the Management of Canara Bank, Bangalore.)

BETWEEN

Shri D. K. Mohan,  
Rep. of Ex-servicemen of Canara Bank,  
No. 6, Muthukumaraswamy Street,  
Perambur, Madras-600011.

AND

1. The General Manager,  
Canara Bank, Head Office,  
P.B. No. 16, No. 112, J. C. Road,  
Bangalore-560002.
2. The General Secretary,  
Canara Bank Employees' Union,  
Moore Street,  
Madras-600001.

Impleaded as per order of this Tribunal in Misc. Application No. 38/89, dated 27-6-89).

REFERENCE :

Order No. L-12011/116/87-D.II(A), dated 19-7-88, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Thiru T. S. Gopalan, Advocate appearing for Respondent No. 1 Management and Thiru R. Arumudham for Tvl. Aiyar & Dolla, Advocates appearing for Respondent Union No. 2 upon perusing the reference, claim and Counter Statements and other connected papers on record and the workman being absent, this tribunal passed the following.

## AWARD

This dispute arises out of a reference under Section 10 (1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by Ministry of Labour, Government of India, for adjudication of the following issue :

"Whether the management of Canara Bank, Bangalore and Canara Bank Employees Union are justified in entering into settlements dated 24-1-81, 5-12-83 and 27-8-86 in so far as they implies adverse alterations of conditions of service in terms of the benefits of service-weightage for promotion and allotment of supervisory duties compare to settlement dated 17-10-73 to the ex-servicemen employees detailed in annexure ? If not, to what relief the said workmen are entitled to ?"

## ANNEXURE-I

List of Ex-servicemen employees of Canara Bank  
Shri

1. D. K. Mohan
2. M. S. Kannappan
3. Ananthakrishnan

4. D. N. Shankaran
5. S. Authithal
6. C. L. Joseph John
7. N. Ramamurthy
8. S. Vishwanathan
9. V. R. Chandran
10. V. K. Srinivasan
11. P. Murugesan
12. G. Ramalingam
13. M. Alagasamy
14. K. Chandran
15. S. Veerasamy
16. M. Anbalgan
17. M. Jayaraj
18. P. Rajaram
19. V. Gopalan
20. R. Sardhar Singh
21. D. Roserl
22. V. Govindan
23. L. Krishnamurthy
24. V. Subramaniyan
25. P. Kathivarayan
26. A. A. Raghavan
27. J. S. Packrarij
28. D. L. Reddi
29. A. Kunjan
30. R. Jayaraman
31. S. Nelson Suganraj
32. P. S. Sundaram
33. A. Victor
34. V. Subramanian
35. A. Amalraj
36. B. Ramamurthy
37. K. Rathinavelu
38. R. Chellappa
39. N. Ramanathan
40. K. Khaja Moimideen
41. K. Kannapiran
42. R. Alagar Ramanujam
43. M. Balasubramaniam
44. K. Sakkari
45. A. Rajashekaran
46. K. Venkatesan
47. K. Palani
48. R. Govindaraj
49. P. Perimananarayanan
50. G. Sivaramakrishna
51. S. Ganapathy
52. L. K. Moorthy
53. D. Robert
54. S. Krishnabarathi
55. V. Govindan
56. N. P. Thirujnana
57. V. Vishwanathan
58. M. Alexander
59. S. Michal
60. Chandran
61. J. S. Amarnath
62. P. Guruswamy
63. R. Perumal
64. D. Gunasekaran
65. K. Ramaraj
66. M. Gnanaraj
67. P. Rajendran
68. K. Narayanan
69. K. Nallakarasu

70. A. Sathasivam
71. S. Rajamanickam
72. A. Amavasi
73. K. Kannappan
74. R. Sadacharan
75. R. Sadacharan
76. V. Navaneetha Krishnan
77. U. Chinnakaruppan
78. M. A. Ismail
79. A. Kunjan
80. R. Jayaraman
81. Subbiah
82. K. Thirumalaivelu
83. K. Ramaraj
84. T. Gunasekharan
85. K. R. Mani
86. A. K. Kutty
87. V. Vasudevan
88. Tholasi
89. V. Saminathan.

D.K. Mohan representing the petitioner called absent. No representation for petitioner in forenoon or in the afternoon session.

Respondent 2's witness is present. Industrial dispute dismissed for default.

Dated, this 2nd day of December, 1993.

THIRU K. SAMPATH KUMARAN, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1993

का. आ. 228.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/84/88-आई आर (बी-III)]

एस.एस.के. राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd December, 1993

S.O. 228.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen which was received by the Central Government on the 21st December, 1993.

[No. L-12012/84/88-I.R. (B-III)]

S. S. K. RAO, Desk Office.

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER  
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL  
CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 34/90

Kashmir Chand Vs. State Bank of India.

For the workman : Shri Tek Chand Sharma.

For the management : Shri Ashok Khullar.

## AWARD

Central Government vide gazette notification No. L-12012/84/88-I.R. (B.III) dated 6-3-90 issued U/S 10(1)(d) of I.D. Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of India, Punjab Region-V, Chandigarh, in terminating the services of Shri Kashmir Chand, Godown Keeper w.e.f. 2-8-80 and not considering him for appointment against future vacancy was justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. Brief facts as enumerated from the statement of claim that the petitioner had worked with the respondent bank from May 1980 to August 1980. The work for which he was employed was of permanent nature. However the management illegally terminated his service on 2-8-1980 without any termination order. No notice was served. No enquiry was held and he was not served any charge sheet. Action of the management in termination of his services is illegal, arbitrary and mala fide and against the mandatory provisions, of Para 522 of Sastri Award and various bi-partite settlement. He also alleged that the management had employed large number of persons after his termination and junior persons were also retained and thus the management has violated the provisions of Section 25-F, 25-G and 25-H of the Industrial Disputes Act, 1947. He thus has sought reinstatement with full back wages.

3. The management has taken the preliminary objection that the claim of the petitioner is stale having raised after number of years. On merits the plea of the management is that the petitioner has worked as godown keeper from 5-5-80 to 2-8-80 for the period of 90 days only. He was engaged purely on temporary basis against seasonal vacancy and not against any permanent regular vacancy. The petitioner being a temporary employee was not subject to any notice of termination. His services automatically ends on the completion of specified period unless gets extended. The plea of the management is that he was engaged temporarily against seasonal vacancy and his services ends automatically, therefore, serving of charge sheet and holding of an enquiry was not required. The action of the management in terminating his services is perfectly legal and justified and he is not entitled to any relief and sought the dismissal of this reference.

4. Replication was also filed, reiterating the claim made in the statement of claim.

5. The petitioner produced himself as WW1 in evidence. He filed his affidavit Ex. W1. MW1 M.P.S. Sandhu, Manager Audit is management's witness. He filed his affidavit Ex. M1. He also relied on the documents Ex. M2 to Ex. M8. The respective parties closed their evidence.

6. I have heard both the parties, gone through the evidence and record.

7. Learned counsel appearing on behalf of the workman has argued that the termination of the petitioner is illegal and has sought the reinstatement with back wages. There is no force in this contention. The petitioner in his own showing was appointed for a fixed period of 90 days from 5-5-80 to 2-8-80. The provisions of Bi-partite Settlement are applicable to the banking industry. Para 20.8 of the said Bi-partite Settlement dated 19-10-1966 which is relevant to the present case is reproduced below :

"20.8 A temporary workman may also be appointed to fill a permanent vacancy provided that such temporary appointment shall not exceed a period of three months during which the bank shall make arrangements for filling up the vacancy permanently. If such temporary workman is eventuality selected for filling up the vacancy the period of such temporary employment will be taken into account as part of his probationary period."

8. It is therefore, apparent that the management is within its competence to appoint temporary workman to fill the permanent vacancy provided that such temporary employment

does not exceed three months during which period the bank was required to make arrangement to fill the vacancy permanently. It appears that this provision for appointment of temporary workman has been made keeping in view of the peculiar nature of the functions of the bank which are customer oriented and there could be wide fluctuation in the volume of work day to day basis. The joining of the petitioner itself for said specified period amounts to giving acceptance. His tenure of employment having only for 90 days and not completing of stipulated one year continuous service as defined in Section 25-B of the Act does not qualify himself under the protection of Section 25-F of the I.D. Act and obviously it was not mandatory for the management to have served a notice or to have pay the wages in lieu of notice and retrenchment compensation to him. Therefore, the management has not contravened any provision of Industrial Disputes Act, 1947 and of the Bi-partite Settlement.

9. Another plea raised by the counsel for the petitioner is with regard to the violation of Section 25-H of the I.D. Act, 1947. No doubt MW1 M.P.S. Sandhu the management's witness in his cross-examination has admitted that after the removal of the petitioner they had been employing temporary workmen like the petitioner. He has also stated that the said employment taken place whenever the contingency had arisen. The same thing is also evident from Ex. M3 to Ex. M8 in which the Employment Exchange send a list of number of workmen required by the bank in the year 1979, 1982 and 1984. But however in the present case the petitioner is heavily burdened to prove the said violation in specific and to adduce sufficient evidence in that regard. In order to attract the same the petitioner is required to prove that specific employment took place at that very post where he was working after his termination. In his pleadings or in his evidence he has not stated as to which person the respondent management had given employment after him and when the said employment had taken place. There is also no evidence that the post still existed even after the termination of the services of the petitioner. In this situation it can not be said that the post against which the petitioner was working continued after the termination of the service of the petitioner. Ratio of judgement in State of Punjab Vs. Ram Murti reported in 1991 (3) Service Cases Today page 127 is followed. Thus the petitioner has failed to prove any violation of Section 25-H of the Industrial Disputes Act, 1947.

10. Hence nothing survive in the proceedings initiated by the petitioner and he is not entitled to any relief whatsoever. Chandigarh, 30-11-1993.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1993

का. ग्रा. 229:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/725/87-डी II (ए)]

एस. एस. के. राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd December, 1993

S.O. 229.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st December, 1993.

[No. L-12012/725/87-D.II(A)]

S. S. K/ RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL-CUM-LABOUR  
COURT, CHANDIGARH

I.D. 83/88

Baldev Singh Vs. State Bank of India.

For the workman : Shri J.B. Garg.

For the management : Shri Ajay Kohli.

## AWARD

Central Government vide gazette notification No. L-12012/725/87-D.II(A) dated 19th October, 1988 issued U/S 10(1)(d) of the I.D. Act referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the State Bank of India, Regional Office, Shimla is not promoting Shri Baldev Singh then field messenger now clerk at their Chamba branch w.e.f. 1-2-1981 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The brief facts in this case is that the petitioner is appointed as field messenger on 16-4-1973 at Dohra branch. According to him four persons namely Ratnesh Chand, P.L. Kondal, K. C. Choudhary and Deep Raj Sharma were appointed as field messenger in the state of Himachal Pradesh. The agreement was reached between the bank and the union and it as settled that all the four employees shall be allowed to sit in the first test to be held hereafter for clerical cadre notwithstanding their having put in five years confirmed service as messengers. The test was held on 5-10-1980. The said four persons were called to appear and were promoted as clerk w.e.f. 1-2-1981. The petitioner has alleged that he was also eligible to appear in the said test. However he was called to appear in the test held on 27-5-1984 and promoted w.e.f. 1-3-1984. He made representation to the management to promote him as clerk w.e.f. 1-2-1981 as had been done in relation to said four persons but no effect. He has thus sought promotion as clerk with retrospective effect from 1-2-1981 on the basis of promotion test held on 5-10-1980.

3. The management in their written statement has taken the stand that the said four persons namely Ratnesh Chand, P. L. Kondal, K. C. Choudhary and Deep Raj Sharma were employed as field messenger in subordinate cadre in the year 1971-72. The said four persons had raised industrial dispute in 1979 for promotion to clerical cadre. In the said industrial dispute an agreement was reached between the said four persons and the bank in which it was agreed that they will be permitted to appear in the special test held on 5-10-1980 for promotion to clerical cadre. They all qualified the test/interview and promoted as clerk w.e.f. 1-2-1981. However the petitioner was neither party to the dispute nor he had at the material time represented for his case being considered alongwith others four persons. He raised this dispute after more than six years from the date of cause of action arose. The said agreement was between the bank and said four persons and not in general. The petitioner cannot claim promotion retrospectively from 1-2-1981. The petitioner successfully cleared the promotion test held on 27-5-1984 and has been duly promoted as clerk on 1-3-1984. The case of the petitioner is without any merit. He cannot validly claim promotion retrospectively from 1-2-1981 and sought the dismissal for the reference.

4. Replication was also filed reasserting the same facts as contained in the claim petition.

5. The petitioner filed his affidavit Ex. W1 in evidence. MW1 D.D. Thapa is the management's witness. He filed his affidavit Ex. M1. The management also relied on the documents Ex. M2 and M3. The respective parties closed their evidence.

6. I have heard both the parties, gone through the evidence and record.

7. The petitioner has based his claim on the basis of settlement and sought his promotion retrospectively w.e.f. 1-2-1981 which is without any merits. The said four persons namely Ratnesh Chand, P.L. Kondal, K. C. Choudhary and Deep Raj Sharma field messengers had raised industrial dispute in the year 1979 for their appointment in the clerical cadre. The said dispute was settled before the A.L.C.(C). The said settlement has been placed on the record. Para 4 of the said settlement is relevant and is reproduced as under :

"All the four employees as aforesaid shall be allowed to sit in the first test to be held hereafter for clerical cadre notwithstanding their not having put in five years confirmed service as messengers."

After perusing the same is evident that the settlement was between the said four persons and the respondent management. Thus the said settlement is binding between the parties inter-se which has entered into settlement. The said four persons by virtue of the said settlement appeared in the test on 5-10-1980 and promoted w.e.f. 1-2-1981. The petitioner has absolutely no locus-sandi to claim any benefit from the said settlement being not party to the same. He apparently did not taken any action in relation to his willingness to appear in the test simultaneously or thereafter. He himself has admitted in cross-examination that he made a reference for the first time in the year 1986 that he may be given promotion with back date. He slept over in making representation for nearly six years. Had the petitioner been interested in appear in the test it would expected from him to make necessary payment representation when the cause of action has arisen. It seems he was never serious about this matter. Admittedly the promotion has been given to him w.e.f. 1-3-1984 by virtue of his passing the test held on 27-5-1984. He is certainly not entitled to claim the promotion with retrospective effect i.e. 1-2-1981 having not passed the test on 5-10-1980 on the basis of which the promotion of said four persons took place w.e.f. 1-2-1981.

8. Hence nothing survive in the proceedings initiated by the petitioner and he is not entitled to any relief whatsoever.

Chandigarh.

2-12-1993.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1993

का. आ. 230:-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/62/88-आई आर (बी-III)]

एस.एस.के. राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd December, 1993

S.O. 230.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 21-12-93.

[No. L-12012/62/88-IR(B-III)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. 1D 21/90

Ramesh Kumar Vs. State Bank of India,

For the workman—Shri Tek Chand Sharma,

For the management—Shri Ashok Khullar.

## AWARD

Central Government vide Gazette notification no. L-12012/62/88-I.R.(B-III) dated 23-2-90 issued U/S 10(1)(d) of I.D. Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the State Bank of India, Jalalabad Branch in terminating the services of the workman Shri Ramesh Kumar, Godown Keeper w.e.f. 3-5-80, and not considering him for appointment against future vacancies in the Bank was justified? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?"

2. Brief facts as enumerated from the statement of claim that the petitioner had worked with the respdt. bank from February, 1980 to May, 1980. The work for which he was employed was of permanent nature. However the management illegally terminated his services on 3-5-1980 without any termination order. No notice was served. No enquiry was held and he was not served any charge sheet. Action of the management in termination of his services is illegal arbitrary and mala fide and against the mandatory provisions of Para 522 of Sastri Award and various bipartite settlements. He also alleged that the management had employed large number of persons after his termination and junior persons were also retained and thus the management has violated the provisions of Section 25-F, 25-G and 25-H of the Industrial Disputes Act, 1947. He thus has sought reinstatement with full back wages.

3. The management has taken the preliminary objection that the claim of the petitioner is stale having raised after number of years. On merits the plea of the management is that the petitioner has worked as godown keeper from 4-2-1980 to 3-5-1980 for the period of 90 days only. He was engaged purely on temporary basis against seasonal vacancy and not against any permanent regular vacancy. The petitioner being a temporary employee was not subjected to any notice of termination. His services automatically ends on the completion of specified period unless gets extended. The plea of the management is that he was engaged temporarily against seasonal vacancy and his services ends automatically, therefore, serving of charge sheet and holding of an enquiry was not required. The action of the management in terminating his services is perfectly legal and justified and he is not entitled to any relief and sought the dismissal of this reference.

4. Replication was also filed, reasserting the claim made in this reference.

5. The petitioner produced himself as WW 1 in evidence. He filed his affidavit Ex. W1, MW1 M.P.S. Sandhu, Manager Audit is management's witness. He filed his affidavit Ex. M1. He also relied on the documents Ex. M2 to Ex. M8. The respective parties closed their evidence.

6. I have heard both the parties, gone through the evidence and record.

7. Learned counsel appearing on behalf of the workman has argued that the termination of the petitioner is illegal and has sought the reinstatement with back wages. There is no force in this contention. The petitioner in his own showing was appointed for a fixed period of 90 days

from 4-2-1980 to 3-5-1980. The provisions of Bipartite Settlement are applicable to the banking industry. Para 20.8 of the said Bipartite Settlement dated 19-10-1966 which is relevant to the present case is reproduced below :

"20.8. A temporary workman may also be appointed to fill a permanent vacancy provided that such temporary appointment shall not exceed a period of three months during which the bank shall make arrangements for filling up the vacancy permanently. If such temporary workman is eventually selected for filling up the vacancy the period as such temporary employment will be taken into account as part of his probationary period".

8. It is therefore, apparent that the management is within its competence to appoint temporary workman to fill the permanent vacancy provided that such temporary employment does not exceed three months during which period the bank was required to make arrangement to fill the vacancy permanently. It appears that this provision for appointment of temporary workman has been keeping in view of the peculiar nature of the functions of the bank which are customer oriented and there could be wide fluctuation in the volume of work on day to day basis. The joining of the petitioner itself for said specified period amounts to giving acceptance. His tenure of employment having only for 90 days and not completing of stipulated one year continuous service as defined in Section 25-B of the Act does not qualify himself under the protection of Section 25-F of the I.D. Act and obviously it was not mandatory for the management to have served a notice or to have pay the wages in lieu of notice and retrenchment compensation to him. Therefore, the management has not contravened any provision of Industrial Disputes Act, 1947 and of the Bipartite Settlement.

9. Another plea raised by the counsel for the petitioner is with regard to the violation of Section 25-H of the I.D. Act, 1947. No doubt MW1 M.P.S. Sandhu the management witness in his cross-examination has admitted that after the removal of the petitioner they had been employing temporary workmen like the petitioner. He has also stated that the said employment taken place when ever the contingency had arisen. The same thing is also evident from Ex. M3 to Ex. M8 in which the Employment Exchange send a list of number of workmen required by the bank in the year 1979, 1982 and 1984. But however in the present case the petitioner is heavily burdened to prove the said violation in specific and to adduce sufficient evidence in that regard. In order to attract the same, the petitioner is required to prove that specific employment took place at that very post where he was working after his termination. In his pleadings or in his evidence he has not stated as to which persons the respdt. management had given employment after him and when the said employment had taken place. There is also no evidence that the post still existed even after the termination of the services of the petitioner. In this situation it cannot be said that the post against which the petitioner was working continued after the termination of the services of the petitioner.

10. However at the stage of argument it has been pointed out by the learned counsel on behalf of the petitioner that one Kashmir Chand was duly appointed on 5-5-1980 at the same branch from where the services of the petitioner was terminated on 3-5-1980, although the preference should be given to the petitioner. He has also pointed out that reference of said Kashmir Chand No 34/90 is also pending in this Court. Representative of the management could not rebut the same. In this situation this Court has taken the judicial notice of the situation. It is apparent that the said Kashmir Chand was no doubt appointed on the same very post after the termination of the services of the petitioner. But the services of said Kashmir Chand was also terminated on 2-8-1980. It is settled law that the retrenched employee has no right of reinstatement and he has only to be given preferential treatment of re-employment over the other candidates as held in Jaswinder Singh Passi and others, the petitioners Vs. The Registrar Co-operative Society Punjab and others reported in 1992 LIC Page 549 and Rajbir Singh and others Vs. The State of Haryana and others reported in 1983 (1) S.L.R. page 38. However since the services of said Kashmir Chand was also terminated w.e.f. 2-8-1980 the

just relief the petitioner can be granted, that he is entitled to the wages equal to the wages paid to above said Kashmiri Chand having the management violated the provisions of Section 25-H of the I.D. Act, 1947.

11. In a way the reference is answered accordingly.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

Chandigarh.  
30-11-1993

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1993

का.आ. 231 :- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु मर्चन्टाइल लि., बम्बई के प्रबन्ध-तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-12012/74/89-आई आर (बी-1)]

एस. एस. के. राव, डेस्क अधिकारी,

New Delhi, the 22nd December, 1993

S.O. 231.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Tamil Nadu Mercantile Bank Ltd., Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 22-12-93.

[No. I-12012/74/89-1R(B)]

S. S. K. RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, BOMBAY

Present :

Shri Justice R. G. Sindhakar,  
Presiding Officer

Reference No. CGIT-45 of 1989

Parties :

Employers in relation to the management of Tamil Nadu Mercantile Bank Ltd., Bombay.

AND

Their workmen

Appearances :

For the Management.—Shri Thakkar, Advocate.

For the Workman.—Shri M. B. Anchan, Advocate.

INDUSTRY : Banking. STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 24th day of November, 1993

#### AWARD

The following reference has been made to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by notification dated 6-10-1989.

“Whether the action of the management of Tamilnadu Mercantile Bank in transferring Mrs. Gowri V. Nathan, clerk from Bombay to Mangalore is

legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”  
It arises this way.

2. On 11-10-1980, the delinquent workman M/s. Gowri Nathan of Ghatkopar, Bombay came to be appointed by the employer namely, Tamilnadu Mercantile Co-op. Bank Ltd., as an apprentice Clerk. The appointment was purely on temporary basis for a period of 5 months from the date of joining the Bank at Bombay Branch on an allowance of Rs. 350 per month. She was to complete all the conditions of appointment as mentioned in the letter of appointment dated 11-10-1980, at Exhibit W-1, within four months from the date of joining duty. It was then only that he was eligible for regular pay after four months. She was to pass successfully a test to be conducted at the completion of two months. Her services came to be confirmed with effect from 1-4-1982 and this was conveyed to her by letter dated 3-5-1982. Thereafter, in the year 1989, her services were transferred to Mangalore Branch of the Bank and this was communicated to her by letter dated 17-5-1989 by the Branch Manager. She was relieved from the Bombay Branch on the closure of that day's business hours and was instructed to join the new place immediately. The Maharashtra State Bank Employees' Federation protested against this act on 18-5-1989 and moved the Asst. Labour Commissioner. The management was called upon to file its say by letter dated 29-5-1989 of the Asst. Labour Commissioner.

3. The management filed its reply on 16-6-1989 and a rejoinder was also filed on 29-6-1989. The conciliation failed and the Asst. Labour Commissioner informed the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi accordingly. It is because of this, the present reference came to be made to this Tribunal for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

4. It so happened that the employee had applied for leave for 13 days from 24-4-1989 to 6-5-1989. According to the management, she did not join duties, on expiry of the sanctioned leave, and, she was therefore, informed by letter dated 10-5-1989, that she has been marked absent with effect from 9-10-1989. She was also informed that she absented herself on 22-4-1989 without applying for leave on 22-4-1989 and 23-4-1989. She was directed to resume duties immediately, failing which she was told that action would be taken against her. Mrs. Gowri Nathan did not join duties but informed the management of her difficulties that she would have faced if she was asked to join at Mangalore, and she also complained about non-payment of salary. The management, on 14-9-1989, gave her a chargesheet, and she was called upon to show cause, failing which disciplinary action was to be initiated. The charges levelled against her were :—

1. Disobedience of the law-ful and reasonable orders of the superiors.
2. Insubordination and,
3. Absenting from duty from 18-5-1989 and thereby committing 'misconduct'.

Enquiry could not be held, because the matter was taken up in conciliation before the Asst. Labour Commissioner.

5. The workman has contended in the statement of claim filed on her behalf by the General Secretary of the Federation (Maharashtra State Bank Employees' Federation) that the transfer order is mala-fide and has been issued by way of victimisation of the employee who was an active member of the Federation in order to discourage upon activities of the new union, and that the transfer order has been issued by the Branch Manager. It is the case of the union, that the Bank Employee's Association was not effective and it was not taking up the grievances of the employees properly with the management. Therefore, the new union namely the Tamilnadu Mercantile Bank Employees' Union was formed. To curb the activities of the union, transfer was effected. According to the union, the transfer order has been issued by the Branch Manager, Bombay, who has no authority to transfer the services.

6. It is further stated that she was not liable for any transfer in the absence of any such condition in her ap-

pointment letter, and that she was appointed to Bombay Branch. It is further stated that no lady has been so far transferred from Bombay to any other place, and that any such transfer is prohibited under the Sastri Award. It is further stated that she is not from Tamilnadu, Karnataka, and that she does not know Kanada language. The federation lastly prayed that for all these reasons, stated above, the transfer is not justified and required to be set aside.

7. Written statement has been filed on behalf of the management contending that the transfer is not mala-fide, and that it has been made considering the business exigencies of the Bank, the reasons such as the employee concerned had worked for about 8 years in the Bank, the delinquent employee was conversant with English, Hindi, Gujarati languages etc., and the management expect customers speaking in these languages at their newly opened branch at Mangalore. Therefore, she was transferred to a place where the need of such an efficient and experienced person was felt. It was further stated that the transfer order was not passed by the Branch Manager, and that it was only conveyed by the Branch Manager to the employee concerned. The management also contended that transfers have been effected several times in the past. Reference was made to the decision of the Supreme Court in the Civil Appeal No. 248 of 1965 between the management of Syndicate Bank and their workmen. The management further contended that the Tamilnadu Mercantile Bank is not a party to the Sastri Award and therefore, the provisions made under the Sastri Award was not applicable in this case. It was further stated by the management that the union has no locus standy to espouse the present reference on behalf of the workman, the reference is bad in law and not maintainable.

8. The contention therefore, is that there is no merit in the grievance of the delinquent employee, and no relief could be granted to her.

9. So far as the leave is concerned, it has been stated that she unauthorisedly remained absent on 22-4-1989 and she also did not get her leave extended for the period after expiry of her sanctioned leave during which she remained absent. She did not report to the place of transfer in spite of being asked repeatedly to do so, and thus she was required to be charge-sheeted. It is also not true that she has been appointed to the Bombay Branch and that her services are not liable to the transferred. The letter dated 11-10-1989, appointing her mentions;

"You are appointed as apprentice Clerk temporarily for five months from the date of joining at our Bombay branch on 6-10-1989."

It is the contention of the management that she was not appointed to work at Bombay branch only, I am inclined to accept this submission. What preceeds the work 'at our Bombay Branch' is to be noted. It says: 'Five months from the date of joining at our Bombay branch'. Therefore, she was to join at Bombay branch, but it speaks of the commencement of period of five months. The said letter dated 11-10-1980 has been issued by the Bank's Head Office at Tuticorin, and a copy of the same has been forwarded to the Bombay Branch. Therefore it is evident that her appointment is to the Bank, and that is also evident that the Bank has in all, as many as 120 branches all over India.

10. It is then contended that the appointment letter does not say that she is liable for transfer. In my opinion, it is not necessary. The appointment was on that basis of the settlements arrived at between the Tamilnadu Mercantile Bank Employees' Association and the Bank management. The Association and the management arrived at on 26-5-1989 a settlement which provides for joining time and travelling allowances on transfer etc. The provisions for transfer of staff members were contemplated. Apart from that, when one is appointed on the establishment of a Bank having as many as 120 branches all over the country, one must assume that one is liable to be transferred. Reference which has been made to the Sastri Award on behalf of the workmen also goes to show that the transfers

are an indispensable part of the Service Conditions. There are Courts' decisions which show that it is the right of the Bank management even under the Sastri Award to transfer any of its employees. It is not necessary to refer to them, because, here the position is well settled. What is to be seen is whether it is mala-fide and by way of victimisation, and the burden of showing this is on the part of the employee. An attempt has been made to show that it is mala-fide and I shall deal with it a little later. However, to contend that she could not have been transferred from Bombay to any other place is, in my opinion, further.

11. It was then contended that the Branch Manager who transferred her was not competent to transfer her. The evidence of Shri Vasudevan, Manager, Bombay Branch, goes to show that the transfer order was passed by the Head Office, by the General Manager, and he only communicated the same to her. The order passed by the General Manager is on record, and it is clear therefrom that it was not the Branch Manager at Bombay who passed the order transferring the delinquent workman from Bombay to Mangalore. The letter dated 17-5-1989 by the Branch Manager is only communicating the order received by the Bombay Branch from the Head Office. It has been specifically mentioned therein, that as per the instructions from the Head Office, she has been transferred to Mangalore Branch. The letter at Exhibit No. M-1 is addressed to the Manager at Bombay Branch and it has been signed by the General Manager, Administration. It is dated 10-5-1989. It says that the employee, Mrs. Gowri Nathan of Bombay Branch is transferred to Mangalore Branch, and he (Manager Bombay) was advised to relieve her with instructions to her to join duties at Mangalore. Therefore, there is no substance in this submission.

12. The next contention is that the transfer order is in violation of Clause 536 of the Sastri Award, Chapter XXVII:

"We direct that in general the policy should be to limit the transfers to the minimum consistent with banking needs and efficiency. So far as members of the subordinate establishment are concerned there should be no transfers ordinarily and if there are any transfers at all they should not be beyond the language area of the person so transferred. We further direct that even in the case of Workmen not belonging to the subordinate staff, as far as possible there should be no transfer outside the State or the language areas in which an employee has been serving except of course, with his consent. In all cases the number of transfers to which a workman is subject should be strictly limited and normally it should not be more than once in a year. We are unable to accept the demand that residential accommodation should be provided by the bank at the new station. The demand for a special house allowance is also rejected."

It is not necessary to state here, that this is the first transfer order after she joined the services in the year 1980.

12. During the course of the cross-examination, she was asked whether she was prepared to go to any other branch in Madras, or to any other place in Tamilnadu. In answer to this, she said that she was not willing to go out of Bombay. In the course of the argument, it was urged on behalf of the workmen, that there would be severe hardship if she was transferred to a far away place inasmuch as she will have to leave her husband and family. There are circumstances which in my opinion cannot be urged and are involved in almost all cases of transfers.

13. Under the provisions of the Sastri Award also the employee can be transferred of course with his consent. Therefore, this also does not prohibit transfers outside the state or language areas. In this present case, there is only one branch in this state and that is at Bombay. Whereas, in other parts of the country, the Bank has 120 branches. Though it is so apparent, the employee in this case wants me to hold that since she was appointed at Bombay Branch, she could not be transferred. If it is so, no transfer could

be ever effected. I do not think that it is possible in view of the observations made in the Sastri Award. It is in evidence that the employee had in her bio-data stated the languages known, and this aspect is not disputed. It is also in evidence that she has worked in the Bank for about 10 years and thus she is an experienced employee, whom the newly started Mangalore branch was very much in need of. Considering all these factors, the management decided to transfer the employee Mrs. Nathan to Mangalore. It may also be stated here, that she was given special training at the Bank's expenses. It therefore, shows the management has made out a clear case for justifying the transfer.

14. As against, this, the case of the union is that she was at the relevant time, Secretary of the newly formed union, and, she was therefore transferred in order to discourage trade union activities. At the first instance it has been admitted by the employee Mrs. Nathan that management was not informed of her selection. Besides, Mr. Vasudevan admitted that he knew that she was the Secretary of the Union, but did not know since when, the new union was formed and if it was from February 1989. Therefore, when the transfer order was passed, the Bank management was not aware that she was the Secretary of the newly formed Union. The contention therefore, that she was victimised, and that she was transferred from Bombay to Mangalore because of her trade union activities is not borne out by the record, and Mr. Vasudevan specifically denies this suggestion.

15. At this stage, I may refer to the correspondence between the parties and the Asst. Labour Commissioner. It shows that the letter dated 8-5-1989 sent by the Federation to the Asst. Labour Commissioner does not mention the fact that Mrs. Nathan was the Additional Secretary of the Union, and she has been victimised by the transfer. It states in para 3 that it is an interstate transfer and it violates the directions in Sastri Award—para 536. In the 6th para, of the same letter, it is stated that the Union has just been formed and it is in the formative stage and our apprehension is that, this is a direct case of victimisation by way of transfer so as to curb development and growth of the trade union movement in the Bank. It thus, does not say that she was the Additional Branch Secretary of the Union, and therefore, victimised. It is, later, on 29-6-1989, that the Union came out with the case that she was transferred merely because, she has been the Additional Branch Secretary of the Union. It is therefore, in my opinion, to say that the order has been passed mala-fide and to victimise one of the leaders of the Union is not substantiated.

16. Some other injustices are said to be done to victimise the members of the Union and during the course of the cross-examination, Mrs. Nathan contended that she was not aware, if Shri Kripashankar Misra was suspended since he was found drunk and had committed a serious Jeep accident. In the case of Neetha Suvarna, she did not know that if there were any complaint from the customers about her rude behaviour. She later on contended that deductions were made from the wages of some of the Union members on the ground that they had remained absent without leave, and that wages were paid to them after the leave was sanctioned. She contended that the leave application of Ms. Neeta Suvarna, Mr. Narayan Galkar, and herself were not sanctioned initially, and they were granted subsequently. She did not know about the allegation that Mr. Misra, Ms. Neeta Suvarna, Galkar, Madhukar and Kapasi were chargesheeted, and yet, denied that they were chargesheeted on true grounds.

17. The submission that the members of the Union have been victimised on several occasions is not substantiated, and in view of her cross examination it is evident that they could not be taken up as instances of discrimination on the ground that they belonged to the Union.

18. The Bank management has right to effect transfers if needed because of the exigencies of service. If there is a case of mala-fide intention on the part of the management in effecting transfers, surely it could be remedied in a reference like the present one. However, in the present case, I find that the management effected the transfer only

because of the exigencies and need to face the customers, and she being an employee with a number of years experience and knowing many languages, her services were very much required, and the transfer was not effected with any mala-fide intentions of by way of victimisation. It is therefore, difficult to direct its withdrawal. The decisions on the point have been stated earlier by me, and I do not think it is necessary for me to quote the same again since the position is well settled.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1993

का.आ. 232—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन ऑइल कारपोरेशन गोवाहटी रिफ़ाइनरी के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, प्रबन्धन में निरिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, गोवाहटी के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-12-1993 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-30011/17/91—घाई आर (विधि)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th December, 1993

S.O. 232.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Guwahati as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Oil Corporation, Guwahati Refinery and their workmen, which was received by the Central Government on 16th December, 1993.

[No. L-30011/17/91-IR (Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

#### ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, GUWAHATI, ASSAM

Reference No. 2(C) of 1992

PRESENT:

Shri J. C. Kalita, B.A. (Hons) LL.B., Presiding Officer, Industrial Tribunal, Guwahati.

In the matter of an Industrial Dispute

#### BETWEEN

The Management of Guwahati Refinery, Indian Oil Corporation, Noonmati, Guwahati.

#### AND

Their workmen Sarvashri Kamini Nath and 3 others,

C/o Refinery Workers' Union, Guwahati Refinery, Noonmati.

#### AWARD

This Reference arising out of the Central Government Notification No. L-30011/17/91-IR (Misc.) dated 5th March, 1992 relates to the dispute indicated in the schedule below—

"Whether the action of the management of IOC Refinery Noonmati in not absorbing/regularising Sarvashri (1) Kamini Nath (2) Arun Kilita, (3) Jadab Das (4) Jadab Kalita having worked in temporary capacity and paid casual daily rate of wages from 1982 to 1989 (with breaks and changing names) is

justified? If not to what relief the workmen are entitled to?"

On receipt of the notification the reference was registered and notices were issued to the parties to file their written statements but no written statement filed by either party.

Today on 18th November, 1993 the learned counsel for management appeared but workmen remained absent. The counsel for management submits that the workmen were absorbed in service and hence no dispute exist now.

Hence, it is held that no Industrial Dispute now exists and an Award is given accordingly on this 18th day of November, 1993 at Guwahati.

J. C. KABITA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1993

का.प्रा. 233 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ओ.एन.जी.सी. के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण ग्रहमदाबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-12-1993 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-30012/41/91-आई प्रार(विविध)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st December, 1993

S.O. 233.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Oil & Natural Gas Commission and their workmen, which was received by the Central Government on 20-12-1993.

[No. L-30012/41/91-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI H. R. KAMODIA, INDUSTRIAL TRIBUNAL, AHMEDABAD

Ref. (ITC) No. 13 of 1992

#### ADJUDICATION:

##### BETWEEN

Oil & Natural Gas Commission  
Vadodara/Mehsana, ...First party.  
Versus

The workmen employed under it ...Second party.

In the matter of promotion of Shri Rajeshkhar S. to the post of Class II (Supervisor HV) in the scale of Rs. 1030—2000 w.e.f. 1-1-1986 etc.

#### APPEARANCES:

Shri K. V. Gadhia, Advocate.—for the first party.

Shri A. S. Kanoor, representative.—for the second party.

#### AWARD

An industrial dispute between the above-named parties has been referred for adjudication under section 10(1) of the I.D. Act, 1947 to the Industrial Tribunal, Ahmedabad by the Desk Officer, Ministry of Labour vide his order No. L-30012-41/91-IR(Misc) dated, 3-7-1992. Subsequently under an appropriate order this dispute has been referred to for adjudication to this Tribunal.

3-GI/94-J0.

2. The dispute relates to the question whether the action of O.N.G.C. Management through Regional Director, Baroda in not promoting Shri Rajashkhar S. to the post of Class-II Supervisor (HV) in the scale of Rs. 1030—2000 w.e.f. 1-1-1986 is legal, proper and justified? If not to what relief the workman Shri Rajashkhar S. is entitled?

3. The second party has in its statement of claim Ex. 4 contended that the concerned workman has joined as Motor Vehicle Driver in the service of the first party on 19-8-68. After a lapse of 12 yrs. he was promoted to the post of Operator Gr. III (HV) on 31-3-1981 in the then pay scale of Rs. 410-720. This pay scale was subsequently revised and ultimately it was revised to Rs. 550—1130. It appears that the Union has put up some demands with the result that on 24th & 25th April, 1986 meeting was held at Delhi, wherein the matter was settled. On the basis of the said settlement a number of employees in the transport discipline were upgraded to the post of Supervisor w.e.f. 1-1-1984, 1-1-1985 and to the Class-II scale w.e.f. 1-1-1986. It appears that union has also put up some demands with the result that settlement was arrived at which is popularly known as 22 yrs. promotion/appointment policy. The terms of settlement are embodied in the statement of claim. On the basis of said terms of settlement Shri H. P. Patel and other who had completed 22 yrs. of service as on 31-12-1985 were promoted to the post of class II w.e.f. 1-1-1986 in the scale of Rs. 1030—2000 whether he was not promoted without any fault attributed to him in any form whatsoever. He made representation in writing as well as visited the offices of the first party on many occasions. Nobody listened to him. Therefore the second party has prayed to direct the first party to declare that its action in not promoting/upgrading the concerned workman to the post of Supervisor (HV) in the pay scale of Rs. 1030—2000 is illegal and improper and unjustified and against the principles of natural justice, and with a further declaration to promote him to the post of Supervisor (HV) w.e.f. 1-1-1986 in the pay scale of Rs. 1030—2000 with all consequential benefits together with interest @12% and cost of this litigation.

3. The first party has resisted the statement of claim of the second party by its written statement Ex. 5. It has inter alia contended that the reference is not at all maintainable and so this Tribunal has no jurisdiction to entertain the reference. The concerned workman is not a workman as defined under section 2(s) of the I.D. Act. It is a body corporate. It has framed rules for service conditions of the regular employees. It is true that the concerned workman joined with the Commission on 19-8-68 as Motor Vehicle Driver. He was promoted as Operator (HV) on 31-3-1981. It has denied the contention in paragraph 7 of the statement of claim and thereby required the second party to prove the same. It has admitted that settlement was arrived at which is popularly known as promotion under 22 yrs. policy. It has denied that Shri H.V. Patel and others were promoted to the post of Supervisor (HV) w.e.f. 1-8-1985. It has further denied that the concerned workman and others were senior to them. It has not admitted that a Trade Test at Mehana on 16-4-1988 was taken for consideration of the post of Supervisor (HV). It has also denied that number of employees of Transport Discipline holding designation of Operator (HV) promoted to the post of Supervisor (HV) with effect from 1-1-1985 and to the Class-II scale w.e.f. 1-1-1986. The second party has to prove that the concerned workman was required to be promoted to the post of Supervisor (HV) in the pay scale of Rs. 700—1430 by an order dated 7-2-1989. It has submitted that requests of the recognised union of the rejected cases under 22 yrs. policy were further reviewed by the High Power Committee constituted by the Regional Director, ONGC, Baroda. In that case the case reviewed. After going through his performance reports/ACRS, the High Power Committee did not find him fit for up-gradation. It has denied that the concerned workman had made representation in writing as well as visited the offices of

the Commission. Therefore on these grounds it has prayed to dismiss the reference with cost.

5. The second party has examined concerned workman at Ex. 28 and Shri Balakrishna Vasudevan at Ex. 22. The first party examined Shri Babubhai Chimanbhai Kansar at Ex. 37. The parties have produced documentary evidence. They rely on the same in support of their respective contentions. I have heard the parties and I have gone through the entire record of the case. The points that arise for my decision in this reference are as under :

#### Points

1. Whether the action of ONGC Management in not promoting Shri Rajashekher S. to the post of Class-II Supervisor (HV) in the scale of Rs. 1030—2000 w.e.f. 1-1-86 is legal, proper and justified.
2. What order?
6. My findings on these points for reasons hereunder are as follows :

#### FINDINGS

1. In the negative.
2. As per last paragraph of this judgement.

#### REASONS

7. Certain facts asserted by the second party are denied by the first party. Therefore it requires to be seen whether the second party has proved these facts. It is an admitted fact that the concerned workman had joined the commission on 19-8-1984. It is further an admitted fact that he was promoted as Operator (HV) on 31-3-1981. However, the first party has denied that he was promoted under Long term promotion policy and moved to the scale of Rs. 440—758. Ex. 17 is the office order promoting the concerned workman in the pay scale of Rs. 410—720. Ex. 18 is another office order dated 25-8-1983, whereby the pay scale of Rs. 410—720 was revised to Rs. 440—758. The name of the concerned is at Sr. No. 46. Thus it is proved that the said pay scale was revised and he was brought over to pay scale of Rs. 440—758. This aspect is thus proved by the second party by Ex. 18. Ex. 19 is the extract from memo of settlement in the year 1983 between the O.N.G.C. and the Unions. It pertains to revision of pay effected thereby. 430—880 and Rs. 440—758 and Rs. 480—820 were all grouped together and were given one revised pay scale of Rs. 550—1130. As per Ex. 18 the concerned workman was placed in the pay scale of Rs. 440—758. He was brought over to the pay scale of Rs. 550—1130. This is clear from Ex. 22. This is an office order dated 7-2-1989. The name of the concerned workman is at Sr. No. 23 promoting him to the pay scale of Rs. 700—1030. Thus the concerned workman was placed in the pay scale of Rs. 700—1030. Now before I discuss the evidence on the record I would like to discuss some decisions cited before me by the learned advocate of the first party. He has drawn my attention to the case reported in Brooke Bond (India) v. Their Workmen 1963 (1) LLJ at page No. 256. It is a Supreme Court case. His contention was that promotion is a managerial function and the Tribunal should not interfere with such managerial function. In this reported case it was held that under the award of the national tribunal the formula required that at a given time, if more than one person are eligible for promotion, seniority should be taken into accounts and should prevail unless the eligible persons are not equal in merits. In the instant case the concerned workman is senior to some persons. His juniors were promoted to Grade-II in the scale of Rs. 1030—2000. Thus it appears that the concerned workman has been superseded. It was the contention of the first party that second party has not contended in the statement of claim about victimisation or unfair labour practice and so this aspect is not affected by the second party. There is no merit in this statement because it is not necessary for the second party to say in so many words in the statement of claim that the concerned workman has been victimised. It will do if such a meaning is snelt out from various contention raised in the statement of claim. The second party has contended

in the statement of claim that it has not promoted the concerned workman in the pay scale of Rs. 1030—2000 without any fault attributed to him in any form whatsoever. It has also contended that his juniors were promoted whereas he was not promoted. His performance was exemplary. Therefore it is contended that the action of the first party in not promoting him to the said pay scale of illegal improper and unjustified. In the instant case the first party has contended that the concerned workman was not promoted having regard to his performance, reports and ACRs. Therefore the first party has attributed some reason for not promoting him to the post in question. Those reasons will have to be taken into consideration. There should be a judicial scrutiny so far as those reasons are concerned. Thereafter my attention was drawn to the case of Shri C. K. Avasthi v. Indian Institute of Technology reported in 1969 LAB IC page 518, wherein it was held that the concerned workman cannot get promotion as of right. It was further held the decision not to promote him cannot amount to imposing a penalty. In the instant case the decision not to promote amounts to imposing a penalty. The first party has contended that having regard to his adverse remarks in the ACRs he was not promoted. Therefore, if there were no ACRs he would have been promoted. This means that as a penalty he was not promoted. It was held in this case that imposition of the penalty assumes existence of right and results in deprivation of that right. There must be a right and that right must be taken away, permanently or temporarily, by way of punishment. In the instant case the right was taken away by way of punishment. It was further held that petitioner was not able to show that he had right to be promoted to the post of Sr. Stenographer, whereas in the instant case the first party has contended that he has a right to be promoted but on account of adverse remarks he was not promoted. Thereafter my attention was drawn to the case of Hindustan Lever Ltd. v. workmen reported in 1974 (1) LLJ page 94, wherein the Labour Court has held that the appellant's refusal to place P. P. Jude in Grade T-4 was not due to victimisation on account of trade union activities of the workman and the said finding is not challenged. So the entire decision was based on a finding of fact and hence this decision will not be applicable to the facts of the present case. Thereafter my attention was drawn to the case of 1992 (2) SCC at page No. 299 between Baikuntha Nath Das v. Chief Dist. Medical Officer, wherein the order of compulsory retirement was held to be not amounting to punishment and hence it was further held that principles of natural justice were not required to be observed in passing the order of compulsory retirement. Therefore this decision will not be applicable to the facts of the present case. Thereafter my attention was drawn to the case of T. K. Rabari v. State Vol. XXIX (2) GJR at page No. 875. The concerned workman has filed a writ petition. The question for consideration was whether there was any remedy available to the workman. The answer was found in the affirmative and hence it was held that High Court cannot be requested to effective extraordinary remedy without workman first exhaust all available remedies to him. In the instant case there is no writ petition by the workman. He has moved the conciliation officer who on the failure of the same, made the reference in question.

8. The first party has examined Shri Babubhai Chimanlal Kansar. His evidence is wholly confined to Ex. 38 to 49. Ex. 38 is a report alleged misconduct by the concerned workman. It appears that he had committed some misconduct on 18-2-86. Now if we go through the written statement there is no mention whatsoever about Ex. 38 to 49. It was not the case of the first party that because of these papers he was not promoted. The deposition of the concerned workman is at Ex. 28. If we go through the cross-examination it will be crystal clear that no a single question was put to him regarding the departmental enquiry conducted against him. Ex. 38 to 49, were produced after the examination of the concerned workman and so he had no reason to believe that these papers will be used against him. As a matter of fact no questions were put to him regarding the same during the course of his cross-examination and that will go to show that even the advocate of the first party did not know about these papers. The cross-examination of the concerned workman was taken on 2-4-1993, whereas the papers were produced on 25-6-93. As the contention regarding those papers were not raised in the written statement they cannot be taken into considera-

tion. It appears that the complaint against the concerned workman was with regard to some incident which took place on 18-2-86. He was required to be promoted on 1-1-1986. Now the incident which had taken place after 1-1-1986 cannot be taken into consideration. For these reasons I am not prepared to take Ex. 38 to 49 into consideration. At the same time the entire deposition of Babubhai Chimanlal Kassar at Ex. 37 pertains to these papers and so this evidence is also wholly irrelevant. It is pertinent to note that the concerned workman has in his deposition at Ex. 28 not touched this aspect in view of the fact that the first party has not taken up such a contention in his written statement. It is held by His Lordship of the Gujarat High Court in the case of SCA No. 531 of 1981 and others decided on 18th June, 1984 that CRs. subsequent to due date of consideration cannot be taken into account. The concerned workman was to be promoted w.e.f. 1-1-1986 whereas the papers at Ex. 38 to 49 pertain to a period subsequent to this date.

9. The main contention of the first party is that there was adverse remark against the concerned workman and that is why he was superseded for promotion. A copy of the said adverse remark is at Ex. 30. It is for the year ending 31st March, 1986 and so it must have been submitted after 1-4-87, with the result that it was not in existence for consideration of the concerned workman for promotion on 1-1-1986 and so it cannot be taken into consideration. Even if it is taken into consideration it should be treated as stale and belated and should not be considered in view of the fact that the said adverse remark was not communicated to the concerned workman. The adverse remark is to the effect that he is very irregular driver and had been found intoxicated on duty. There is nothing on the record to show that this adverse remark was communicated to him. The concerned workman has said in his deposition that he had never received this adverse remark. The first party has not examined at person to say that adverse remarks were communicated to him. The first party has not produced any evidence to show that the concerned workman had received copy of these adverse remarks. It is a question of fact. Therefore it has got to be proved like any other fact. The first party has not proved this fact and so the adverse remarks cannot be taken into consideration. In the aforesaid Gujarat High Court jurisdiction it was held that the adverse remarks of 3 years prior to due date of consideration if not communicated should be treated as stale and belated and should be ignored for consideration. It was held in the case of Gurdial Singh v. State of Punjab reported in A.I.R. 1979 SC at page No. 1622 that principle is well-settled that in accordance with the rules of principles of natural justice the adverse report in confidential roll cannot be acted upon to deny promotional opportunities unless it is communicated to the person concerned so that he has an opportunity to improve his work and conduct or to explain the circumstances leading to the report. In the instant case it is not proved that adverse remarks were communicated to the concerned workman and so it cannot be taken into consideration. This is the only ground on which the concerned workman has been deprived of his right of promotion. Hence if the adverse remarks at Ex. 30 cannot be taken into consideration there remains nothing against the workman, with the result that he has got to be promoted to the post in question. It is to be noted that in spite of such an adverse remark, the concerned workman was called for Trade test. Ex. 20 is the letter addressed to him. Thereby he was called upon to remain present for Trade test on 16-4-88 in the Transport Campus. Accordingly he reported for Trade test on that date. Now if he was an irregular driver and found to be intoxicated at times he could not have been called for Trade test. The fact that he was called for Trade test will go to show that the said adverse remarks were not at all taken into consideration or were ignored. The concerned workman had passed Trade test. This is an important aspect. It has got to be taken into consideration. That will go to show that he was found to be efficient in the Trade test and so he was qualified for promotion. He was qualified for promotion and that is why he was thereafter again called for interview. Ex. 21 is the letter of interview. He was required to remain present for interview, on 1-12-1988. It was an oral interview. All these facts will therefore go to show that the concerned workman was duly qualified for promotion and that is why he was called for Trade test and had passed Trade test with

the result that he was called for interview. It is also important to note that he had passed interview. However, it appears that for some reason he was avoided. The first party bank upon Ex. 30 as the piece of evidence to deny promotion to him. However, I have already mentioned that Ex. 30 which are adverse remarks were not communicated to him. Therefore the concerned workman was entitled to promotion in the scale of Rs. 1030-2000 alongwith others who were promoted vide office order Ex. 23. Therefore the action of the first party in not promoting the concerned workman to be post in question was illegal improper and unjustified. Therefore I answer point No. 1 in the negative.

10. It was submitted by on behalf of the second party that though the copy of the reference has been sent to Regional Director, O.N.G.C. Western Region, Makarpura Baroda he has not appeared and thus the decision should be taken ex parte against him. There is no merit in this because the Regional Director is not named in the copy sent to him. He has got no independent existence. He has but not joined in his personal capacity. The copy has been sent to him in his capacity as Regional Director and so whoever is Regional Director has to come before the Tribunal. Now the Regional Director is nothing but a director of O.N.G.C. and O.N.G.C-I has but joined as a party. It means that Regional Director is included in O.N.G.C., with the result that it is not necessary to join Regional Director. Therefore there is no merit in this submission. In the result I pass the following order.

#### ORDER

The action of the first party in not promoting the concerned workman Shri Rajashekhar S. to the post of Class-II Supervisor (HV) in the scale of Rs. 1030-2000 w.e.f. 1-1-1986 is not legal and justified and so he is deemed to have been promoted to the said post in question from 1-1-1986 and he shall be paid back wages w.e.f. 1-1-1986. The first party is directed to pay Rs. 250 by way of costs to the second party and bear its own.

Sd/-

SECRETARY.

Ahmedabad,

Dated : 6th December, 1993.

H. R. KAMODIA, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1993

का.प्र. 234 :- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूची में, केन्द्रीय सरकार टूटीकोरन पोर्ट ट्रस्ट, के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, सम्बन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-44012/1/93-आई आर (विविध)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st December, 1993

S.O. 234.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Tuticorin Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on 20th December, 1993.

[No. L-44012/1/93-IR (Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU  
MADRAS

Thursday, the 2nd day of December, 1993

## PRESENT :

Thiru K. Sampath Kumaran, B.A.B.L., Presiding  
Officer.

Industrial Dispute No. 63/93

(In the matter of the dispute for adjudication under Section  
10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the  
Workman and the Management of Tuticorin Port Trust  
Tuticorn)

## BETWEEN

Smt. T. N. Andal,  
C/o R. Rangaraja Iyengar,  
T.C. 41, 1211,  
(New T.C. 40/566),  
Ram Nivas East Puthan Street,  
Manacad P.O.,  
Trivandrum.

## AND

The Chairman,  
Tuticorin Port Trust,  
Tuticorn-628004.  
Tamil Nadu.

## REFERENCE :

Order No. L-44012/1/93-IR (Misc.), dated 15th July,  
1993, Ministry of Labour, Government of India,  
New Delhi.This dispute coming on this day for final disposal, upon  
perusing the reference and other connected papers on record  
and the Workman being absent, this Tribunal passed the  
following

## AWARD

This dispute arises out of a reference under Section 10(1)(d)  
by Ministry of Labour, Government of India, for adjudica-  
tion of the following issue :"Whether the action of the Management of Tuticorin  
Port Trust in removing Smt. T. N. Andal, from the  
services with effect from 27th April, 1989 is justi-  
fied? If not, to what relief she is entitled?"Petitioner called absent. Further time refused. Passed over.  
Again called at 5.10 p.m. No representation for Petitioner.  
Petitioner called absent. Industrial dispute dismissed for de-  
fault. No costs.

Dated, this 2nd day of December, 1993.

THIRU K. SAMPATH KUMARAN, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1993

का.मा. 235 :- औद्योगिक विवाद अधिनियम,  
1947 (1947 का. 14) की धारा 17 के अनुसरण में,  
केन्द्रीय सरकार एम्प्लाइस स्टेट इन्श्योरेंस कारपोरेशन के  
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच,  
अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार  
औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती  
है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-12-1993 को प्राप्त हुआ  
था।

[सं. एल 15012/8/87-डी II(बी)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st December, 1993

S.O. 235.—In pursuance of Section 17 of the Industrial  
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government  
hereby publishes the award of the Central Government Indus-  
trial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the in-  
dustrial dispute between the employers in relation to the man-  
agement of Employees State Insurance Corporation and their  
workmen, which was received by the Central Government on  
20th December, 1993.

[No. L-15012/8/87-D.II(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU  
MADRAS

Wednesday, the 24th day of November, 1993

## PRESENT :

THIRU K. SAMPATH KUMARAN, B.A.B.I., Presiding  
Officer

Industrial Dispute No. 42/1988

(In the matter of the dispute for adjudication under Section  
10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the  
Workmen and the Management of Employees State Insurance  
Corporation, Madras)

## BETWEEN

Miss. L. Anuradha,  
No. 10, Ratchanayapuram,  
Tuticorin-628001.

## AND

The Regional Director,  
Employees State Insurance Corporation,  
ESIC House,  
Sterling Road,  
Madras-600034.

## REFERENCE :

Order No. L-15012/8/87-D.II(B), dated 15th/18th July,  
1987, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.This dispute coming on this day for final disposal upon per-  
using the reference, claim and counter statements, and other  
connected papers on record and the parties being absent, this  
Tribunal passed the following award.

## AWARD

This dispute arises out of a reference under Section 10(1)(d)  
of the Industrial Disputes Act, 1947 by Ministry of Labour,  
Government of India, for adjudication of the following issue:"Whether the action of the Regional Director, Employees  
State Insurance Corporation, Madras in terminating  
the services of Miss. L. Anuradha Ex. LDC Em-  
ployees State Insurance Corporation, Coimbatore  
with effect from 22nd August, 1993 is justified? If  
not, what relief the said workman is entitled to?"Petitioner and respondent called absent (10.41 a.m.) Passed  
over.Petitioner and Respondent called absent. (1.15 p.m.).  
Industrial dispute dismissed for default. No costs.

THIRU K. SAMPATH KUMARAN, Presiding Officer

## आदेश

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1993

का.आ. 236 :—जबकि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की दिनांक 22 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1697 के अधीन गठित श्रम न्यायालय संख्या, 1, धनबाद का पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हुआ है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री पी. के. सिन्हा को 27 नवम्बर, 1993 (पूर्वाह्न) से उक्त श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[सं. ए-11016/8/92-सी.एल.एस.-II]

गोपाल सिंह, अवसर सचिव

## ORDER

New Delhi, the 21st December, 1993

S.O. 236.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal No. 1 at Dhanbad constituted by the Government of India in the Ministry of Labour vide Notification No. S.O. 1697, dated the 22nd May, 1965;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri P. K. Sinha, as the Presiding Officer of the said Labour Court, with effect from the 27th November, 1993 (forenoon).

[F. No. A-11016/8/92-CLS. II]

GOPAL SINGH, Under Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1993

का. आ. 237 :—जबकि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की दिनांक 11 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का. आ. 103 के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण संख्या-1, धनबाद के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हुआ है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री पी. के. सिन्हा को 27 नवम्बर, 1993 (पूर्वाह्न) से उक्त औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[सं. ए-11016/8/92-सी. एल. एस-II]

गोपाल सिंह, अवसर सचिव

## ORDER

New Delhi, the 21st December, 1993

S.O. 237.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal No. 1 at

Dhanbad constituted by the Government of India in the Ministry of Labour vide Notification No. S.O. 103 dated the 11th January, 1960;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri P. K. Sinha, as the Presiding Officer of the said Industrial Tribunal, with effect from the 27th November, 1993 (forenoon).

[F. No. A-11016/8/92-CLS. II]

GOPAL SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1993

का. आ. 238 :—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार डा. (सुश्री) प्रफुल्ला करकेटा, अवसर सचिव को दिनांक 7-12-93 से प्रगला आदेश जारी होने तक उत्प्रवास संरक्षी-1 दिल्ली के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ए-22012/1/92-उत्प्रवास]

सी. डी. भारद्वाज, अवसर सचिव

New Delhi, the 22nd December, 1993

S.O. 238.—In exercise of the powers conferred by Section 3, Sub-Section (1) of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby appoints Dr. (Miss) Prafulla Kerketta, Under Secy. as Protector of Emigrants-I Delhi with effect from 7th December, 1993 till further orders.

[No. A-22012/1/92-Emig]

C. D. BHARDWAJ, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1993

का. आ. 239 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बम्बई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-12-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/180/91-आई आर (डी यू) (पी टी.)]

के. वी. बी. उष्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd December, 1993

S.O. 239.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M.T.N.L. Bombay, and their workmen, which was received by the Central Government on 22nd December, 1993.

[No. L-40012/180/91-IR (DU)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL NO. I, BOMBAY

## PRESENT:

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.  
Reference No. CGIT-36 of 1992

## PARTIES:

Employers in relation to the management of Mahanagar  
Telephone Nigam Ltd., Bombay.

## AND

Their Workmen.

## APPEARANCES:

For the Management—No appearance.

For the Workmen—Workman present in person.

INDUSTRY : Telephone. STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 12th day of November, 1993

## AWARD

By letter dated 7th May, 1992, Government of India, Ministry of Labour, New Delhi has made following reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Mahanagar Telephone Nigam Ltd. Bombay in terminating the services of Smt. Lalitha Mahendra Kamble, Casual/Typist w.e.f. 16th November, 1984 is justified? If not, what relief she is entitled to?"

2. Statement of claim has been filed by the workman. She states that, she worked as Casual Labour in Prabhadevi Exchange from 1st March, 1983 to 15th November, 1984. She performed the duties of a typist. Her services were terminated from 1st November, 1987 and she was not permitted to resume duties nor given any notice pay and/or retrenchment compensation as per the provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947. She approached Regional Commissioner of Labour. She prays for reinstatement in service with full back wages.

3. The management has filed reply to this statement of claim. She was, according to the management, a purely daily rated Casual Labourer engaged every month on "need basis". She was not given any letter of appointment. A regular clerk was working in this unit and there was no need for a second one.

4. It is further stated that she was not removed from service. On the contrary, she remained absent without any intimation. The question of serving any notice did not arise. Her request to the Divisional Engineer was replied.

5. The point that would arise is whether the termination, so styled in the schedule, was justified. According to her, she was not assigned any duties, she was not permitted to resume duties and was not given any notice pay and/or retrenchment compensation as per the provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act. In other words, her case is that because of non compliance of the provisions of section 25F of the Act, retrenchment is illegal and therefore, amounted to termination. As against this, the management has stated that she herself remained absent without any intimation and there is no case of termination or removal. It is to be seen, therefore, whether there was retrenchment. It has been defined in section 2(cc) of the Act as meaning the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include voluntary retirement of the workman on reaching age of superannuation and termination of service as a result of the non-renewal of

the contract or termination of service on the ground of continued ill-health. Here it is not seen that her case comes within the definition of retrenchment. In para 2 she says that she worked as a casual labour and between 1st March, 1983 to 15th November, 1984. The management has stated that she was purely daily rated casual labourer engaged every month on 'need basis'. There is, therefore, the absence of evidence to show that she was appointed on the regular basis and attracting the provisions of 2(cc) of the Act.

6. It is also not seen that she worked for 240 days continuously as defined in section 25(B) of the Act. The workman shall be said to be in continuous service for a period of one year, if he/she is, for that period, in uninterrupted service, including service which may be interrupted on account of sickness or authorised leave or an accident or a strike which is not illegal, or a lock-out or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the workman. This is not the case here. For a period of one year, if the workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than; (i) one hundred and ninety days in the case of a workman employed below ground in a mine; and (ii) two hundred and forty days, in any other case. At any rate there is no evidence to that effect. However, in the letter dated 6th February, 1991, addressed to the Regional Labour Commissioner, she has stated that due to maternity and the sickness of the small children and self she could not report on duty immediately. Therefore, sub-section (1) section 25(B) is not attracted. Again, she must have worked for 240 days in 12 calendar months. Though, it is so stated in that letter in para 3, there is no material to show that. Even in this statement of claim she has not so mentioned. Therefore, she cannot be said to have worked for 240 days in preceding 12 calendar months. If it is so held then section 25(F) will not be attracted nor will section 25(N) be attracted. If it be so question of compliance with the provisions of section 25(F) will not arise. It would not, therefore, amount to a case of termination of service. I stated earlier the management case was that she remained absent without any intimation. That appears to be so from her own statement in letter dated 6th February, 1991 to which reference has been made above. She stated "as submitted earlier, I have worked as Casual Labourer with MTNL, Bombay, from 1982 to 1984 November. Due to maternity and the sickness of the small children and self I could not report on duty immediately. When I approached the office I was told there is a ban, and that I cannot be taken back on duty". It will clearly show that from November, 1984 till middle of 1985, she was not working. I therefore, find the action cannot be said to be unjustified.

7. She has stated though not in the statement of claim in her communication to the management and the Regional Labour Commissioner generally serving workmen are taken up for employment and she has been discriminated. She has produced a zerox copy of circular dated 28th October, 1991 issued by General Manager, MTNL to all General Managers and Deputy General Managers, MTNL, Bombay. That speaks of providing employment to Casual Mazdoors. It has a reference to those who had completed continuous service of 240 days during any 12 calendar months before 30th March, 1985. But that is not the point before me. Providing employment to such persons is not an issue referred to this Tribunal. I am sure the management will take into consideration this aspect and take appropriate action in accordance with this circular dated 20th October, 1991, and give relief to the workman if she is found eligible under that circular. It appears prima facie that she is eligible. Copy of this order be sent to General Manager, MTNL by name.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1993

का. प्रा. 240.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ठ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या

का. प्रा. 1519 दिनांक 22 जून, 1993 द्वारा ताँबा खान उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 10 जुलाई, 1993 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोग सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 10 जनवरी, 1994 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/7/89-आई. आर. (नीति)]

एस. एस. पराशर, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd December, 1993

S.O. 240.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 1519 dated the 22nd June, 1993 the Copper Mining Industry to the public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 10th July, 1993;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 10th January, 1994.

[No. S-11017/7/85-D.I.(A)]

S. S. PRASHER. Under Secy.

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1993

का. प्रा. 941.—केन्द्रीय सरकार में यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1601 दिनांक 2 जुलाई, 1993 द्वारा मैन्नेसाइट खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 3 जुलाई, 1993 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था —

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 3 जनवरी, 1994 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/8/85-डी-1 (ए)]

एस. एस. पराशर, अवर सचिव

New Delhi, the 24th December, 1993

S.O. 241.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 1601 dated the 2nd July, 1993 the Magnesite Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from 3rd July, 1993;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 3rd January, 1994.

[No. S-11017/85/D.I.(A)]

S. S. PRASHER. Under Secy.

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1993

का. प्रा. 242.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 16-1-1994 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है (और अध्याय-5 और 6) धारा-76 की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध गुजरात राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

“जिला भरूच के भरूच तालुका में भरूच नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र तथा ग्राम भोलव, जाडेश्वर बड़ादाव, नन्देलव, तथा जी. आई. डी. सी. भोलव की राजस्व एवं पंचायत सीमा के जिला तथा तालुका भरूच के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र”।

[संख्या एस-38013/32/93-एसएस I]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd December, 1993

S.O. 242.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 16th January, 1994 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Gujarat, namely :—

"Areas within the Municipal limits of City Bharuch, Taluka and District Bharuch and within the revenue and Panchayat limits of Villages Bhelav, Zadeswar Vadadav, Nandelav including Industrial Estate and GIDC Estate Bhelav, Taluka and District Bharuch".

[No. S-38013/12/93-SS.I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1993

का. ग्रा. 243.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) के अधीन बनाए गए रेल कर्मचारी (नियोजन के घण्ट) नियम, 1961 के नियम 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय संयुक्त सचिव, श्री एस. एस. शर्मा को उक्त नियम के तहत अपील सुनने के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. मं. एस.-66012/7/93-औ. सु. व स्वा. I]

राम-तिलक पाण्डेय, उप सचिव

New Delhi, the 23rd December, 1993

S.O. 243.—In exercise of the powers conferred by rule 4(2) of Railway Servants (Hours of Employment) Rules, 1961 under the Indian Railway Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby notifies Shri S. S. Sharma, Joint Secretary

in the Ministry of Labour as Appellate Authority to hear appeals under the said Rules.

[File No. S-66012/7/93-ISH-I]

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1993

का. ग्रा. 244.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिकाधिकारियों को अगले आदेशों तक मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक नियुक्त करती है:—

1. श्री तपन कान्ति मंडल
2. श्री उमेश कुमार शर्मा
3. श्री एलपुला जयाकुमार
4. श्री सुभाषीष राय
5. श्री मुनी राम मांडवे
6. श्री चेरुकुरी रमेश कुमार

[सं. ए-12025/4/91-माई. एस. एच-I]

राम तिलक पाण्डेय, उप सचिव

New Delhi, the 24th December, 1993

S.O. 244.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) the Central Government hereby appoints the following officers as Inspector of Mines Subordinate to the Chief Inspector of Mines, until further orders :—

1. Shri Tapan Kanti Mandal
2. Shri Umesh Kumar Sharma
3. Shri Elpula Jaya Kumar
4. Shri Subhashis Roy
5. Shri Muni Ram Mandve
6. Shri Cherukuri Ramesh Kumar.

[A-12025/4/91-ISH-I]

R. T. PANDEY, Dy. Secy.